घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 220- गुरूवार 11- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मोदी का बतौर पीएम 4399 दिन का कार्यकाल,नेहरू का रिकॉर्ड टूटा....

निर्वाचित पीएम का सबसे लंबा कार्यकाल मेरा सौभाग्य यह सभी कार्यकर्ताओं की उपलब्धि : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,10 जून 2026। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के आज 4,399 दिन पूरे हो गए। मोदी कहा...इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना भगवान की विशेष कृपा से संभव हो सकता है। मेरे लिए जनता ही ईश्वर का रूप है। मैंने सेवा को साधना के रूप में देखा है। ये साधना भी एकाकी नहीं,एक सामूहिक यज्ञ है। यह सभी कार्यकर्ताओं की उपलब्धि है। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। अभी उनका यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम ने कहा...अब देश की जनता एक स्थित सरकार का काम देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। साल 2014 में जब एनडीए जीती तब मैंने कहा कि आज देश के लोगों मे नई आशा का उदय हुआ है। मोदी ने कहा...हमें आज संतोष और गर्व है कि एनडीए परिवार ने इस भरोसे को और मजबूत किया है।

मोदी देश के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले इलेक्टेड पीएम

मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने लगातार 4,399 दिन पूरे कर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब भी नेहरू के नाम है। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी करीब 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे। इनमें 1952 के पहले आम चुनाव के बाद 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक का उनका निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल शामिल है।

मोदी बोले...मेड इन इंडिया जहाज और प्लेन बनाएगा भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में पिछले 12 सालों में काफी काम हुआ है। अब 500 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को तेजी से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत मेड इन इंडिया जहाजों और कंटेनरों के जरिए व्यापार करेगा। मोदी ने कहा कि देश ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है और जल्द ही मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा।

इजराइल,इथियोपिया समेत कई देशों के नेताओं ने पीएम को बधाई दी...

इजराइल,इथियोपिया और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और इजराइल की अनूठी दोस्ती हर साल और मजबूत हो रही है। मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा करने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय जनता के मोदी के नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाती है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज आर्थिक प्रगति और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनने जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं।

140 करोड़ देशवासियों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के शुभकामना संदेश के लिए आभार जताते हुए कहा कि देश ने सालों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं,वे 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास और आकांक्षाओं का परिणाम हैं। उन्होंने कहा- 140 करोड़ भारतीयों का स्नेह और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति और प्रेरणा है।

मोदी के 12 साल पर अभिनंदन प्रस्ताव,शुभेंदु ने झालमुड़ी खिलाई

एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारत मंडपम में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रखा, जबकि नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने इसका समर्थन किया। बैठक में भाजपा-एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य नेता शामिल हुए। सभी ने मोदी को बधाई दी। बैठक के बाद मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ झालमुड़ी भी खाई। इससे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में भी सर्वसम्मति से बधाई प्रस्ताव पारित किया गया और मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं।

एकनाथ शिंदे बोले...पीएम मोदी के 12 साल का कार्यकाल बेदाग और ऐतिहासिक

एनडीए बैठक में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए के 12 साल केवल सत्ता में रहने के नहीं,बल्कि राष्ट्रसेवा के प्रति निरंतर समर्पण के रहे हैं। उन्होंने कहा... कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल का कार्यकाल बेदाग और ऐतिहासिक रहा है,जिसमें उन्होंने देश के लिए लगातार काम किया और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। शिंदे ने कहा कि मोदी केवल राजनीतिक नहीं,बल्कि एनडीए नेताओं के साथ पारिवारिक संबंध भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में विकास को '2014 से पहले' और '2014 के बाद' के नजरिए से देखा जाता है,और इसके पीछे मोदी का दिन-रात काम करने वाला नेतृत्व है।

पश्चिम बंगाल में विभागों का बंटवारा....

शुभेंदु ने संभाला गृह,भूमि व ऊर्जा,स्वपन दासगुप्ता को वित्त,अग्निमित्रा को शहरी विकास

कोलकाता,10 जून 2026। पश्चिम बंगाल की नई सरकार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का विस्तृत बंटवारा कर दिया है। राज्य सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभागों के आवंटन के साथ ही नई सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग, भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग,विद्युत विभाग, सूचना एवं संस्कृति विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सहित वे सभी विभाग अपने पास रखे हैं, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की

आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और भूमि संबंधी नीतियों पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी रहेगी। निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग तथा जल संसाधन जांच एवं विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विपणन विभाग का मंत्री बनाया गया है। खुदिराम टुडू को जनजातीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामले विभाग तथा मदरसा शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अग्निमित्रा पॉल को शहरी विकास एवं नगर मामलों के विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं, दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा विभाग, आवास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं वस्त्र विभाग का प्रभार दिया गया है। तापस राय को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग तथा गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. शंकर घोष को संसदीय कार्य विभाग और पर्यटन विभाग सौंपा गया है।

मोदी सरकार के 12 साल पर कैबिनेट का बड़ा फैसला

अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार को मंजूरी....

नई दिल्ली,10 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल होने के मौके पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार के साथ कई अहम फैसले लिए। मोदी मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2ए के तहत 6.032 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसमें पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड होंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फेज 2(ए) के चालू होने की जानकारी दी। अहमदाबाद-गांधीनगर में 77.63 किलोमीटर का एक्टिव मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। फेज 2(ए) कॉरिडोर में स्टेशनों के नाम हैं- आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और एयरपोर्ट। प्रोजेक्ट के लिए आईडीसी (कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्याज) सहित कुल पूरा होने की लागत 2,169.04 करोड़ रुपये होगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज 2(ए) शहर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला विकास होगा। यह बेहतर कनेक्टिविटी, कम ट्रैफिक जाम, पर्यावरण के फायदे, आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर क्वालिटी देने का वादा करता है। शहर की

मुख्य चुनौतियों का समाधान करके और भविष्य में विस्तार के लिए एक आधार प्रदान करके, फेज 2(ए) शहर के विकास की राह और स्थिरता को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2ए निर्माण गतिविधि की चरम अवधि के दौरान लगभग 2,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा और सिस्टम के संचालन और रखरखाव के दौरान 500 लोगों के काम करने की संभावना है। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज 2(ए) शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ी तरक्की दिखाता है। फेज 2(ए) शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क के एक बड़े विस्तार के तौर पर काम करता है। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में लगभग 6.032 किलोमीटर का नया मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जिसका मकसद एयरपोर्ट तक आसान कनेक्टिविटी देकर और उन खास रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों को जोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी बेहतर बनाना है, जहां अभी अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। इस फेज का मकसद रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब समेत खास जोन को मौजूदा अहमदाबाद-गांधीनगर कॉरिडोर के साथ आसानी से जोड़ना है। इसके अलावा, वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2029 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए आस-पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी डेवलप होने की संभावना है। वैष्णव ने कहा कि इन जरूरी इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़कर, फेज 2(ए) न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि आर्थिक गतिविधि, पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और रहने वालों और विजिटर्स दोनों के लिए शहरी गतिशीलता को आसान बनाएगा। मेट्रो रेल एक अच्छा दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट है और फेज 2(ए) मेट्रो रेल नेटवर्क को एयरपोर्ट तक बढ़ाने के साथ, अहमदाबाद के अंदर खास तौर पर असरदार होगा।

कैबिनेट ने अमरावती में दो बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में दो प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए जनरल पूल ऑफिस आवास (सीजीजीपीओए) और कर्मचारियों के लिए जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास (जीपीआरए) शामिल हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना का विकास करना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अमरावती में केंद्रीय सरकारी जनरल पूल ऑफिस आवास परियोजना को 1,299.08 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। इस परियोजना में 23.25 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा। साथ ही जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1,234.91 करोड़ रुपये है और इसमें 31.30 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा। उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाएं सस्टेनेबल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों पर आधारित होंगी। इनमें न्यूनतम एकीकृत आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग (गृहा) 4-स्टार रेटिंग सुनिश्चित की जाएगी और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी 2024) के अनुरूप डिजाइन तैयार किया जाएगा। भवनों को ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

केंद्र ने 30 जून से प्लास्टिक नोट के दावे को नकारा,कहा- कागजी नोट नहीं बदलेंगे

नई दिल्ली,10 जून 2026। सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि केंद्र सरकार 30 जून से कागजी नोट हटा देगी और उसकी जगह प्लास्टिक के नोट जारी किए जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने अपना जवाब दिया है और ऐसे दावों को पूरी तरह झूठ बताया है। प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हवाले से बताया कि 30 जून, 2026 तक कागजी मुद्रा नोटों को वापस लेने या उन्हें प्लास्टिक मुद्रा नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में यह झूठा दावा किया जा रहा है कि 30 जून से आरबीआई कागजी मुद्रा नोटों को वापस लेकर उनकी जगह प्लास्टिक मुद्रा नोट जारी करेगा, यह दावा फर्जी है। आरबीआई के अनुसार, 30 जून तक कागजी मुद्रा नोटों को वापस लेने या उन्हें प्लास्टिक नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है। पीआईबी ने प्रामाणिक जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट एचटीटीपी://आरबीआई.ओआरजी.आईएन देखने को कहा है।

मसूरी में भीषण सड़क हादसा...गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तार कार,चार की मौत

मसूरी,10 जून 2026। उत्तराखंड के मसूरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। जहां, एक तेज रफ्तार कार झड़ीपानी शॉर्टकट मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया है। जबकि अन्य तीन की तलाश जारी है। एसडीआरएफ को खाई में घनी झाड़ियां होने के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ की टीम करीब 600 मीटर गहरी खाई में उतरकर चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान चला रही है। प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। एसपी सिटी ने बताया कि कार हादसे में चार लोगों की मौत की सूचना है। रेस्क्यू टीम शवों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभियान पूरा होने के बाद शवों को बाहर निकालकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सोनिया गांधी का मास्टरस्ट्रोक! ममता बनर्जी को कांग्रेस में विलय का ऑफर,बढ़ी सियासी हलचल

नई दिल्ली,10 जून 2026। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के भीतर मचे घमासान ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तृणमूल कांग्रेस के कुल 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए अपना एक अलग गुट तैयार कर लिया है। पार्टी में यह असंतोष सिर्फ राज्य स्तर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां टीएमसी के करीब 20

सांसदों ने पार्टी से दूरी बना ली है। इस भारी टूट ने तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और पार्टी पूरी तरह बिखरने की कगार पर पहुंच गई है। पार्टी के भीतर मचे इस भारी घमासान और बगावत के बीच, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला ऑफर दिया है। इस राजनीतिक संकट से उबरने के लिए सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में पूरी तरह से विलय करने का प्रस्ताव दिया है। इस विलय के बदले में कांग्रेस आलाकमान ने ममता बनर्जी को राजनीति में सम्मानजनक स्थान देने का वादा किया है। इस रणनीतिक विलय के बदले में सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के सामने एक आकर्षक संगठनात्मक ढांचा पेश किया है। सूत्रों का कहना है कि यदि टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है, तो ममता बनर्जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा।

नीति आयोग की बैठक आज,केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर होगी चर्चा

नई दिल्ली,10 जून 2026। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गयी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाने, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन,साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों के बेहतर उपयोग पर चर्चा होगी। नीति आयोग के अनुसार इस वर्ष बैठक का विषय 'विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास' रखा गया है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के समग्र विकास और कल्याण के लिए साझा रणनीति तैयार करना है। बैठक प्रधानमंत्री मोदी के 'टीम इंडिया' के विजन के अनुरूप आयोजित की जा रही है। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि विकसित भारत के लक्ष्य को ठोस और मापनीय परिणामों में कैसे बदला जाए ताकि देश के हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके। बैठक में समावेशी मानव विकास ढांचे के चार प्रमुख स्तंभों पर चर्चा होगी। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य-पोषण एवं कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा शामिल हैं।

बेजुबान जानवरों की भलाई जरूरी है मूकदर्शक नहीं बना जा सकता,सुप्रीम कोर्ट ने रमन की कस्टडी केरल सरकार को सौंपी

नई दिल्ली,10 जून 2026। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबसे लंबे हाथी रमन के कमर्शियल इस्तेमाल की बुराई की है,जबकि इस तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया गया था। इस बात पर जोर देते हुए कि वह इस तरह की नाफरमानी पर आँखें नहीं मूंद सकता और जब बेजुबान जानवरों की भलाई की बात हो तो मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को हाथी की भलाई को लेकर उसे कुछ समय के लिए अपनी कस्टडी में लेने का निर्देश दिया। कैद में रखे गए हाथी रमन को लेकर विवाद लंबा और उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जो ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट में कई दौर की

केस लड़ चुका है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राज्य को रमन को एक सही रेस्क्यू या रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश दिया। जस्टिस शर्मा, जिन्होंने बेंच की ओर से फैसला लिखा, ने कहा, यह सच में बहुत बुरा है कि जिस हाथी की बात हो रही है, यानी रमन जो केरल का सबसे लंबा हाथी भी है,उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इस तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश है और वह भी इस कोर्ट के सामने दिए गए अंडरटेकिंग के आधार पर।

मप्र से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी,तीनों भाजपा उम्मीदवारों के नाम शामिल

भोपाल,10 जून 2026। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन रिक्त सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए बुधवार को संवीक्षा (स्क्रूटनी) के बाद बुधवार को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों - तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। इनमें दो सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते की है। इन तीन सीटों के लिए भाजपा के तीन उम्मीदवार-तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल तथा कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन भाजपा की आपत्ति के बाद हलफनामे में अनियमितताएं पाए जाने के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन मंगलवार को खारिज कर दिया गया था।

टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा,असम के मुख्यमंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली,10 जून 2026। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मिलने पहुंचीं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन्होंने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को लिखे इस्तीफे में कहा कि वह तत्काल प्रभाव से राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें सभापति, उपसभापति और राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों से सहयोग मिला, जिसके लिए वह आभारी हैं। सुष्मिता देव का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब टीएमसी पहले से ही अंदरूनी असंतोष और नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं का सामना कर रही है। सबसे पहले मई के महीने में राज्य विधानसभा में पार्टी हाईकमान ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन, पार्टी के 80 में से 58 विधायकों ने पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ

जाकर बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुना था। इसके बाद पार्टी के 28 लोकसभा सदस्यों में से लगभग 20 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को समर्थन देने और अलग गुट बनाने की इच्छा जताई थी। इसे पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। टीएमसी में सुष्मिता देव से पहले भी कई इस्तीफे और टूट दर्ज किए गए हैं। सबसे हाल में 8 जून को वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दिया था।

संपादकीय

सरकारी तंत्र में भटकती जवाबदेही

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12 वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ी के बाद जब केंद्र सरकार ने इस संस्था के चेयरमैन राहुल सिंह को उनके पद से हटाया तो ऐसा लगा कि अंततः उसने अपनी किरकिरी कराने वाले इस मामले में जवाबदेही तय करना आवश्यक समझा,लेकिन जल्द ही खबर आई कि उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया। आखिर यह कैसी कार्रवाई और जवाबदेही? इस तबादले से उनकी सेहत पर क्यों असर पड़ने वाला? उनके साथ सीबीएसई के सचिव पद से हटाए गए हिमांशु गुप्ता को उनके मूल कैडर भेज दिया गया। संभवतः कुछ समय तक केंद्र में उन्हें प्रतिनियुक्ति न मिले, लेकिन इसे भी किसी तरह की कठोर कार्रवाई कहना कठिन है। सीबीएसई मामले में तो फिर भी दो अधिकारियों का तबादला किया गया। इससे अधिक गंभीर नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में तो कुछ भी नहीं किया गया। इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के किसी अधिकारी का न तो स्थानांतरण हुआ और न ही निलंबन। यह तब है,जब सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि इस मामले में जवाबदेही तय किए बिना इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता।

नीट पेपरलीक मामले में सरकार और विशेष रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस के अलावा बीते दिनों काकरोच जनता पार्टी ने भी दिल्ली में प्रदर्शन कर उनका इस्तीफा मांगा। यह ठीक है कि यह प्रदर्शन फीका रहा और वह कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया,लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नीट पेपरलीक मामला गंभीर नहीं और सरकार की जवाबदेही की जरूरत खत्म हो जाती है। चूंकि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में किसी गड़बड़ी या गलती के लिए किसी मंत्री का त्यागपत्र नहीं लिया गया,इसलिए शिक्षा मंत्री के भी इस्तीफे के कोई आसार नहीं। कहना कठिन है कि मोदी सरकार अपने इस तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल करेगी या नहीं और जब ऐसा होगा तो कसौटी पर खरा न उतर पाने या सरकार की किरकिरी कराने वाले मंत्रियों की छुट्टी होगी या नहीं,लेकिन नीट पेपरलीक बहुत ही गंभीर मामला है।

दोबारा परीक्षा देने के तनाव में कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं? यह सही है कि किसी बड़ी गलती-गड़बड़ी या घटना-दुर्घटना के कारण यदि किसी अधिकारी को बर्खास्त किया जाता है अथवा किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो जाता, लेकिन जब ऐसा होता है तो जन भावनाओं को संतुष्टि मिलती है और लोगों का रोष एवं आक्रोश कम होता है। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो सवाल उठता है कि आखिर जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है या नहीं?

बात केवल परीक्षाओं में गड़बड़ी और उसके चलते लाखों छात्रों के परेशान होने और उनमें से कुछ के आत्महत्या करने की ही नहीं है। अन्य अनेक मामलों में भी सरकारी तंत्र की जवाबदेही बड़ी मुश्किल से तय होती है। इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली में अवैध तरीके से बने और अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चल रहे होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत की। इनमें से कई विदेशी थे, जो अपने परिवार वालों के उपचार के लिए दिल्ली आए थे। 22 लोगों की मौत के बाद होटल के मालिक और रसोइए को तो गिरफ्तार कर लिया गया,लेकिन नगर निगम,अग्निशमन विभाग आदि के किसी कर्मचारी-अधिकारी का निलंबन तक नहीं किया गया, जबकि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आखिर दोषी केवल होटल मालिक नहीं, जिसने छह की जगह 25 कमरे बना लिए। दोषी तो वे सब भी हैं, जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिया। किसी इमारत में अवैध रूप से छह से 25 कमरे बना लेना कोई ऐसा काम नहीं कि उसे कोई देख न पाए। साफ है कि भ्रष्टाचार के चलते यह अवैध होटल बना और चला। क्या यह निराशाजनक नहीं कि दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन उसके तहत काम करने वाली सरकारी एजेंसियों का कार्य-व्यवहार नहीं बदला?

हम इस पर गर्व करते हैं और करना भी चाहिए कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बड़ा ही है,बेहतर नहीं और इसका एक प्रमुख कारण है सरकारी तंत्र में जवाबदेही का अभाव। इस अभाव के चलते जिस तरह बार-बार एक जैसे कारणों से परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होते रहते हैं,वैसे ही अवैध निर्माण होते रहते हैं अथवा नई बनी सड़कें दोयम दर्जे के निर्माण के कारण ध्वस्त हो जाती हैं। इसी तरह करीब-करीब सभी शहरों में एक जैसे कारणों से हादसे होते रहते हैं,जिनमें लोग मरते भी हैं। कभी यह सामने आता है कि किसी जर्जर इमारत को दो से चार मंजिल का बना दिया गया और कभी यह कि आग की चपेट में आया कोई होटल या रेस्त्रां अवैध तरीके से संचालित हो रहा था और उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं थे। यहां तक कि अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं था। यदि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है,सुशासन को सचमुच स्थापित करना है और भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो शासन तंत्र का जवाबदेह होना आवश्यक ही नहीं,अनिवार्य है।

पचास के बाद पेरेंट्स और बच्चे का भविष्य

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

देर से संतान,जल्दी चिंताएँ?

विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएँ और संभावनाएँ प्रदान की हैं। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति ने उन दंपतियों के लिए भी माता-पिता बनने का मार्ग खोल दिया है,जो किसी कारणवश प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्ति में सक्षम नहीं थे। आईव्हीएफ(इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) जैसी तकनीक ने हजारों परिवारों को संतान सुख दिया है। निःस्संदेह यह आधुनिक चिकित्सा की एक बड़ी उपलब्धि है। किंतु हर उपलब्धि के साथ कुछ प्रश्न और जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। आज जब कुछ दंपति 50-52 वर्ष या उससे अधिक आयु में,कभी-कभी कर्ज लेकर,आईव्हीएफ के माध्यम से माता-पिता बनने का निर्णय लेते हैं, तब इस विषय पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है।

संतान की इच्छा मनुष्य की सबसे स्वाभाविक और गहरी भावनाओं में से एक है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना परिवार हो,घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें और जीवन को एक नई दिशा मिले। इसी चाहत के कारण अनेक दंपति वर्षों तक उपचार करवाते हैं और आर्थिक तथा मानसिक संघर्ष झेलते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन माता-पिता बनना केवल बच्चे के जन्म तक सीमित नहीं है। वास्तविक जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। बच्चे को जन्म देना अपेक्षाकृत आसान है, किंतु उसे एक जिम्मेदार,शिक्षित और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।

जब कोई दंपति 50 वर्ष की आयु में माता-पिता बनता है,तो यह स्वाभाविक है कि जब बच्चा बारहवीं कक्षा में पहुँचेगा,तब माता-पिता की आयु लगभग 68 से 70 वर्ष के बीच होगी। यह जीवन का वह चरण होता है जब अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बाद आरामदायक जीवन की अपेक्षा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह,थायराइड,हृदय रोग,गठिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ सामान्य हो जाती हैं। ऐसे में बच्चे की पढ़ाई, करियर और भावनात्मक जरूरतों के लिए पहले जैसी सक्रियता बनाए रखना आसान नहीं होता।

किशोरावस्था और युवावस्था किसी भी बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होती है। इसी अवधि में उसे सही मार्गदर्शन,आत्मविश्वास और भावनात्मक सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी,उच्च शिक्षा का चयन, करियर की योजना और जीवन से जुड़े अनेक निर्णय इसी उम्र में लिए जाते हैं। यदि उस समय माता-पिता स्वयं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों,तो बच्चे और परिवार दोनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। कई बार बच्चे को अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के साथ-साथ माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।

इस विषय का एक सामाजिक पक्ष भी है। विद्यालयों और सामाजिक आयोजनों में बच्चे अपने मित्रों और सहपाठियों के बीच रहते हैं। कई बार उम्रदराज माता-पिता होने के कारण बच्चों को अनावश्यक टिप्पणियों या मजाक का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि यह समाज की अपरिपक्वता का परिचायक है,फिर भी इसका प्रभाव बच्चे के मनोविज्ञान पर पड़ सकता है। बच्चे अक्सर अपने साथियों के बीच स्वयं को सहज और स्वीकार्य महसूस करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ कभी-कभी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी देर से मातृत्व-पितृत्व कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। आईव्हीएफ उपचार पर लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं। अनेक परिवार इसके लिए अपनी बचत समाप्त कर देते हैं या ऋण लेते हैं। इसके बाद बच्चे के पालन-पोषण,शिक्षा,स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं पर निरंतर खर्च होता है। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना पहले की तुलना में कहीं अधिक महंगा हो चुका है। यदि माता-पिता पहले से आर्थिक दबाव में हों और सेवानिवृत्ति के निकट हों,तो भविष्य में बच्चे की उच्च शिक्षा और करियर निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना कठिन हो सकता है। महिलाओं के संदर्भ में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकृति ने प्रजनन के लिए एक जैविक समय-सीमा निर्धारित की है। रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज इस बात का संकेत है कि शरीर प्रजनन क्षमता के अंतिम चरण में पहुँच चुका है। आधुनिक चिकित्सा तकनीकें इस सीमा को कुछ हद तक आगे बढ़ा सकती हैं, किंतु वे उम्र से जुड़ी सभी चुनौतियों को समाप्त नहीं कर सकतीं। अधिक आयु में गर्भधारण और प्रसव के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालाँकि इस विषय पर चर्चा करते समय संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। यह मान लेना उचित नहीं होगा कि अधिक आयु में माता-पिता बनने वाला हर व्यक्ति अपने बच्चे के लिए समस्या बन जाएगा। अनेक लोग 60 वर्ष की आयु में भी पूरी तरह स्वस्थ, सक्रिय और आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। वहीं कई युवा माता-पिता भी अपने बच्चों को पर्याप्त समय और संसाधन नहीं दे पाते। इसलिए किसी निर्णय का मूल्यांकन केवल उम्र के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन औसत परिस्थितियों को देखते हुए आयु एक महत्वपूर्ण कारक अवश्य है,जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में गोद लेने का विकल्प भी विचारणीय है। हमारे देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश माता-पिता के स्नेह और संरक्षण से वंचित हैं। यदि सक्षम परिवार उन्हें अपनाएँ,तो न केवल उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है,बल्कि परिवारों को भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्य से आज भी समाज में जैविक संतान को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण अनेक लोग गोद लेने जैसे सकारात्मक विकल्प पर गंभीरता से विचार नहीं करते।

वास्तव में माता-पिता बनने का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करना नहीं है। इसका अर्थ है आने वाले बीस-पच्चीस वर्षों तक बच्चे के जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाना,उसके सपनों को समर्थन देना और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहना। इसलिए संतान प्राप्ति का निर्णय लेते समय केवल वर्तमान की खुशी नहीं,बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। भावनाएँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दूरदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है। अंततः प्रश्न आईव्हीएफ या चिकित्सा विज्ञान का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपने निर्णयों के दीर्घकालिक परिणामों पर पर्याप्त विचार कर रहे हैं। संतान जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है,लेकिन वह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसलिए देर से मातृत्व-पितृत्व का निर्णय लेने से पहले स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और सबसे बढ़कर बच्चे के भविष्य को केंद्र में रखकर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी बच्चे का सर्वोत्तम हित ही हर निर्णय का आधार होना चाहिए। यही परिपक्व अभिभावकत्व की पहचान है।

अदालत में रसूख का खेल

अमीर को बेल...गरीब को जेल...

अजय कुमार,
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर आम आदमी के मन में हमेशा से एक गहरी उलझन रही है। कानून की किताबों में लिखा है कि न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी बंधी होती है, यानी वह अमीर-गरीब,बड़े-छोटे,मशहूर-गुमनाम सबको एक तराजू पर तौलती है। लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इस आदर्श की धज्जियां उड़ाती नजर आती है। जब कोई आरोपी समाज में लोकप्रिय हो,उसके पीछे लाखों अनुयायियों की भावनाएँ जुड़ी हों और उसकी जेब में महंगे वकीलों की फौज खड़ी करने की ताकत हो,तो अदालत का रुख भी कई बार उस सामान्य आरोपी से एकदम अलग दिखाई देता है,जो न तो मशहूर है और न जिसके पास साधन हैं। पटना में 2 जून की घटना ने इस पूरे सवाल को एक बार फिर ताजा कर दिया,जब कदमकुआं थाना क्षेत्र में स्थित ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी और खान सर के कोचिंग संस्थान के बीच विवाद हुआ,मारपीट हुई और फायरिंग भी हुई। इस पूरे मामले में पटना जिला न्यायालय ने चर्चित शिक्षाविद और लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद मउआर ने पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। दूसरी ओर, उसी मामले में एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और वे फिलहाल जेल में बंद हैं। इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई और उनका मामला अभी लटका हुआ है। यानी जो लोग कह रहे थे कि उन्होंने खान सर के कहने पर हवा में गोली चलाई,वे जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो व्यक्ति उन पर आरोप लगा रहे थे, वह न्यायालय से संरक्षण पाकर आजाद घूम रहे हैं।

यह विरोधाभास सिर्फ इस एक मामले तक सीमित नहीं है। भारतीय न्यायिक इतिहास में ऐसे अनेक प्रकरण दर्ज हैं, जहाँ आरोपी की सामाजिक हैसियत, उसकी लोकप्रियता या उसकी आर्थिक ताकत ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। वर्ष 2002 में सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का मामला चला। दशकों तक चले इस मुकदमे में राजस्थान की निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया,लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे पलट दिया। इस पूरे दौर में यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि एक मशहूर अभिनेता को कोई साधारण व्यक्ति जैसी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। जमानत तत्काल मिली,सुनवाई टलती रही और आखिरकार वे बरी हो गए। इसी तरह संजय दत्त के हथियार मामले में भी कई दशकों तक न्यायिक प्रक्रिया चली। जेल में समय बिताया जरूर,लेकिन हर मोड़ पर कानूनी राहत मिलती रही। राजनीतिक रसूख वाले आरोपियों का किस्सा तो और भी लंबा है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए, किंतु उनकी बीमारी और अन्य आधारों पर बार-बार जमानत मिलती रही। जगन मोहन रेड्डी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हुई, लेकिन उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई और बाद में वे मुख्यमंत्री बन गए। इन सब में एक धागा,जो एक-सा नजर आता है, वह है बड़े और दिग्गज वकीलों की भूमिका।

भारत में कानूनी पेशे की एक कड़वी सच्चाई यह है कि न्यायालय में बहस के कौशल के साथ-साथ वकील का नाम, उसका रुतबा और संबंध भी उतने ही अहम हो जाते हैं। जब कोई बड़ा वकील किसी मामले में पैरवी करता है, तो अदालत का माहौल ही बदल जाता है। उसकी दलीलें उसी तथ्य को एक नए कोण से प्रस्तुत करती हैं,जिसे एक साधारण वकील शायद ढंग से कह भी नहीं पाता। वह जमानत की पात्रता,धाराओं की प्रकृति,पूर्व के न्यायिक निर्णयों और संविधान के प्रावधानों को इस प्रकार पिरोता है कि न्यायाधीश के सामने उसका मुवक्किल निर्दोष नहीं तो कम से कम संदेह के दायरे में जरूर आ जाता है। खान सर के मामले में भी उनके वकील ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने दबाव बनाने के लिए हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम जैसी गंभीर धाराएँ लगाई हैं और घटना में कोई व्यक्ति गोली लगने से घायल नहीं हुआ। यह तर्क कितना सफल रहा, यह अदालत के आदेश से साफ हो गया। बड़े वकीलों का दबाव केवल दलीलों तक सीमित नहीं होता। कई बार यह दबाव प्रक्रियागत चालाकी के रूप में सामने आता है। सुनवाई को टालना,नई याचिकाएँ दाखिल करना, एक के बाद एक उच्च न्यायालयों में जाना और अंततः उच्चतम न्यायालय तक पहुँचना, ये सब वे औजार हैं जिनका इस्तेमाल कर बड़े मुकदमों में समय खरीदा जाता है। जब तक मुकदमा चलता रहता है, आरोपी या तो जमानत पर बाहर रहता है या फिर जेल में भी वे सुविधाएँ हासिल कर लेता है,जो एक साधारण कैदी की कल्पना से परे होती हैं। इसके अलावा,प्रसिद्ध वकीलों के पास न्यायपालिका के भीतर के अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि न्यायाधीश खरीदे जाते हैं, क्योंकि ऐसा प्रमाण बिरला ही मिलता है, किंतु एक अनुभवी न्यायविद यह जरूर जानता है कि कौन-सी अदालत,कौन-सा पीठ और कौन-सा दिन उसके मुवक्किल के लिए अनुकूल हो सकता है।

आम आदमी जब इन सब बातों को देखता है,तो उसके मन में न्याय के प्रति आस्था डगमगाने लगती है। वह देखता है कि एक सुरक्षा गार्ड, जो किसी के आदेश पर काम कर रहा था,जेल में है। एक संस्थान का निदेशक, जिसने शायद इसी तरह का काम किसी और के इशारे पर किया हो, जेल में है। लेकिन जो व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है और जिसके सुरक्षाकर्मियों ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने उसके कहने पर हथियार चलाए,वह न्यायालय के संरक्षण में आजाद है। यह दोहरापन न्यायिक व्यवस्था की उस बड़ी कमजोरी को उजागर करता है, जिसे सुधारने की बात हर दशक में होती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। न्याय का सिद्धांत कहता है कि संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। अग्रिम जमानत का प्रावधान इसीलिए बना है ताकि किसी निर्दोष को बिना कारण जेल की यातना न भोगनी पड़े। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यही प्रावधान चुनिंदा लोगों के लिए ढाल बन जाता है और बाकी सब उसी कानून की तलवार के नीचे खड़े रहते हैं। जब तक न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक गरीब और अमीर आरोपी के बीच का फर्क अदालत के भीतर भी मिटाया नहीं जाएगा, तब तक भारत की न्याय प्रणाली आम आदमी के लिए टेढ़ी खीर ही बनी रहेगी।

निर्मलता

प्रिया देवांगन प्रियू
गरियाबंद छत्तीसगढ़

पहले हमें लोग कितना मानते थे
जीजी! घाट पर आकर प्रतिदिन दीप
जलाते, स्नान कर के अपने शरीर को
शुद्ध करते; साथ ही साथ किनारे
बैठ कर ठंडी-ठंडी पुरवाई का आनंद
भी लेते थे। कितने अच्छे दिन
थे....पैरी की आँखें भर आईं।
हाँ! पैरी बहन दुःख-सुख बाँटते,
अब न पेड़ों की छाया न कोई
इंसान। कूड़ादान बना रखा है हमें।
आप कैसी हैं जीजी...दोनों बहनों ने
बड़ी जीजी से पूछने की हिम्मत
जुटाई।
हाँ बहनों! मेरा भी यही हाल है, अब
मेरे जल में स्नान करने लोग कभी-
कभी ही आते हैं और उसके बाद भी
लोग अपने-अपने घरों में या पास
लगे नलकूपों से स्वयं को पुनः
पवित्र करते हैं । इंसानों की
सुविधाएं हमें और भी पीछे छोड़ती
नजर आ रही हैं। चारों तरफ सूखा
ही सूखा है। इतना कह करे बड़ी
जीजी का गला भर आया। ख़ैर
छोड़ो..लोग जैसे भी रहें लेकिन हमें
अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए।
हमारा जल आज भी पवित्र है और
कल भी रहेगा;उनके गंदगी फैलाने
से हम गंदे नहीं हो जाएंगे, अभी भी
लाखों जीव हमारे अंदर रह कर
जीवन यापन कर रहे हैं, हमें उन पर
भी ध्यान देना चाहिए न! क्या हुआ
शहरों में गंदगी है तो...आगे जंगलङ्क
झरनों में तो हमारा जल पवित्र है ही।
आज भी अमृत है। सदैव अच्छी
सोच रखो बहनों। हाँ! जीजी लेकिन
हमारी इतनी पतली धार में इन बेचारे
नन्हे जीवों का जीवन खतरे में है
इनका क्या करें? इतना बोलते ही
जोरों की बारिश होने लगी। भगवान
ने हमारी व्यथा सुन ली जीजी! फिर
क्या.... महानदी, पैरी और सोंढूर
तीनों बहनों की पतली धारा, मोटी
धारा में बदल कर एक-दूसरे में
समाहित होकर मुस्कुराते हुए मंजिल
की तरफ प्रवाहित होने लगीं।

भीषण गर्मी में महिलाओं की बढ़ती परेशानियाँ

डॉ विजय गर्ग

गर्मी का मौसम हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह चुनौती कई बार अधिक गंभीर रूप ले लेती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान,लगातार पड़ने वाली लू और लंबी होती गर्मी की अवधि ने महिलाओं के स्वास्थ्य, कामकाज और दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के सामने गर्मी से जुड़ी समस्याएँ अधिक जटिल रूप में उभर रही हैं। महिलाएँ घर और बाहर दोनों स्थानों पर अनेक जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे खेतों में काम करती हैं, पशुओं की देखभाल करती हैं, पानी और ईंधन जुटाती हैं तथा घर के अन्य कार्य भी संभालती हैं। जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुँच जाता है, तब इन कार्यों को करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण शरीर में पानी की कमी, थकान, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भीषण गर्मी और भी अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक गर्मी गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं को बढ़ा सकती है। इससे उच्च रक्तचाप, निर्जलीकरण तथा समय से पहले प्रसव जैसी समस्याएँ उत्पन्न होने की आशंका रहती है। कई शोध यह भी संकेत देते हैं कि लगातार उच्च तापमान माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं की परेशानियाँ कम नहीं हैं। घरों में खाना बनाते समय रसोई का तापमान पहले ही अधिक होता है। जब बाहर का तापमान भी अत्यधिक बढ़ जाता है, तब रसोई में काम करना और कठिन हो जाता है। कई निम्न आय वर्ग के परिवारों में एयर कंडीशनर तो दूर, पर्याप्त पंखे और शीतलन की सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होतीं। परिणामस्वरूप महिलाओं को लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहना पड़ता है। गर्मी का प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लगातार गर्मी, नींद की कमी, कार्यभार और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण तनाव, चिड़चिड़ापन और चिंता की समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

चापलूसी का बोलबाला

लक्ष्मीनारायण सेन
गरियाबंद,छत्तीसगढ़

मोहन और सोहन दोनों परम मित्र है।एक दूसरे के बैगेर ये दोनों रहा नहीं करते। दोनों साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक ही कालेज में करते। दोनों के विचार राष्ट्रवाद था। दोनों जब भी खाली समय में बैठते तो देश समाज पर हो रही समकालीन घटनाओं पर चर्चा करते। चूंकि दोनों घर से सक्षम थे इस कारण किसी नौकरी के तरफ ध्यान नहीं दिये। दोनों अपना सिविल कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ करता है।

अब दोनों मित्र एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। दोनों की पार्टी बैठक में आना जाना प्रारंभ हो जाता है । दोनों बैठक में सकारात्मक अभिमत देता है।एक दिन एक योजना की निर्माण पर चर्चा हो रहा था तो पार्टी अध्यक्ष ने सबसे अपना अभिमत मांगा तो सभी ने अध्यक्ष के बातों का समर्थन किया पर, सोहन अपना तर्क के माध्यम से इस योजना को जनहितकारी में असंभव बताया। सोहन के बात से अध्यक्ष महोदय नाराज रहता है पर सोहन को कुछ कहता नहीं। मोहन का आदत चाटुकारिता प्रवृत्ति का होता है।कुछ दिन बाद पार्टी में विभिन्न पदों का नियोजन होता है जिसमें मोहन को सहसचिव का पद मिलता है पर सोहन को कोई पद नहीं दिया जाता फिर भी सोहन शांत रहता है और पार्टी और जनता के लिए कार्य करते रहता है।

कुछ बरस उपरांत स्थानीय निकाय की चुनाव की बारी आती है। यहां पर भी टिकट हेतु सोहन ठगा जाता है, और मोहन को पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। सोहन का मन कुछ समय के लिए विचलित हो जाता है फिर शांत हो जाता है। अब चुनाव में सोहन को चार जोन का दायित्व दिया जाता है,सोहन खूब मेहनत करता है और चारों जोन की उम्मीदवार विजय भी हो जाता है।पर पार्टी अधिकांश सीट हार जाता हैं यहां तक की उनके मित्र मोहन भी हार जाता है। चुनाव के बाद चुनाव परिणाम की समीक्षा होती है। इस समीक्षा बैठक में सोहन अपने मन का भड़ास निकालता है सबके सब चुपचाप सुनता है। किसी के मुख से कोई जवाब नहीं निकलता क्योंकि सोहन के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था।

चुनाव परिणाम के समीक्षा बैठक के बाद पार्टी के कुछ पदों का नियोजन होता है। इसमें सोहन को भी पद दिया जाता है पर यह पद उनके योग्यता के अनुकूल नहीं था क्योंकि यह पद कनिष्ठ सदस्य के लिए उपयुक्त था अतः सोहन पुनः ठगा जाता है और पद लेनें से मना कर देता है।बड़ी विडंबना थी उससे कनिष्ठ सदस्यों को उससे वजनदार पद दे दिया जाता है।सोहन थोड़ा नाराज होता है और शांत हो जाता है। चूंकि सोहन का उद्देश्य पार्टी का पद लेना या विधायक सांसद बनना नहीं था केवल उनका उद्देश्य राष्ट्र व जनता का सेवा करना था। अतः बिना पद के ही निष्ठापूर्वक सोहन राष्ट्र और जनसेवा का कार्य करता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

CMYK

खरीफ से पहले किसानों की चिंता बढ़ी...खाद संकट,बढ़े बिजली बिल और डीजल की दिक्कत पर किसान कांग्रेस का हल्ला बोल

9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,कहा...सरकार की नीतियों से छोटे किसानों पर आजीविका का संकट...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जून 2026
(घटती-घटना)।

खरीफ सीजन की दस्तक से पहले खाद,बीज और सिंचाई जैसी मूलभूत जरूरतों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर सरगुजा जिला किसान कांग्रेस ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में किसान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता और ग्रामीण अध्यक्ष नागेश्वर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद की उपलब्धता में कटौती,खाद-बीज संकट, बिजली बिल में वृद्धि, डीजल की उपलब्धता और फसलों के भुगतान में देरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

खाद की कमी से उत्पादन और आजीविका दोनों पर संकट

किसान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही खाद संकट गहराने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण किसानों को आवश्यक उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो इसका सीधा असर धान उत्पादन पर पड़ेगा और लाखों किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि सरगुजा सहित पूरे प्रदेश के छोटे और सीमांत किसान खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में खाद की कमी केवल कृषि उत्पादन का नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी बड़ा संकट बन सकती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की, हेमंत सिन्हा, मोहम्मद इस्लाम,विनय शर्मा,इंद्रजीत सिंह धंजल, अमित सिंहदेव,बलराम यादव,रामविनय सिंह, मदन जायसवाल,अनिल सिंह,डॉ. लालचंद यादव,संजीव मंदिलवार,आलोक सिंह,ए.पी. सांडिल्य, रशीद अहमद,संजय सिंह,शिवभरोष बेक,लुकस एक्का,कलीम अंसारी सहित बड़ी संख्या में किसान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बिजली बिल बढ़ा,खेती की लागत भी बढ़ी...

ग्रामीण अध्यक्ष नागेश्वर यादव ने कहा कि किसान पहले ही बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। अब बिजली दरों में वृद्धि ने खेती की लागत को और बढ़ा दिया है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान सीमा किसानों की जरूरतों के अनुरूप नहीं है।

डीजल प्रतिबंध से किसान परेशान...

किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नुरुल अमीन सिद्दीकी ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर जरीकैन में डीजल देने पर लगाए गए प्रतिबंध का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों तक ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरणों के लिए डीजल इसी माध्यम से ले जाते हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल इस प्रतिबंध में राहत देने की मांग की।

फसल बिक्री के बाद एकमुश्त भुगतान की मांग...

ज्ञापन में धान खरीदी के बाद किसानों को भुगतान की प्रक्रिया सरल बनाने की भी मांग की गई है। किसान कांग्रेस का कहना है कि किसानों को फसल बिक्री के बाद पूरा भुगतान एकमुश्त मिले, ताकि उन्हें खेती और पारिवारिक जरूरतों के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

किसान कांग्रेस की प्रमुख मांगें...

- खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- खाद-बीज संकट का तत्काल समाधान किया जाए।
- बिजली बिल वृद्धि वापस ली जाए या किसानों को राहत दी जाए।
- डीजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की जाए।
- धान खरीदी के बाद किसानों को एकमुश्त भुगतान किया जाए।
- कृषि लागत कम करने के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए।
- छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाए।
- खरीफ सीजन के लिए कृषि इनपुट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

खरीफ की तैयारी के बीच बढ़ी बेचैनी

सरगुजा में खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे समय खाद की उपलब्धता को लेकर उठे सवाल और बढ़ती कृषि लागत किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इसका असर आगामी धान उत्पादन पर पड़ सकता है।

आंधी-बारिश से मोहनपुर में भारी नुकसान

पेड़ गिरने से मकान ढहा,सड़क पर अवरोध,बिजली व्यवस्था भी प्रभावित

-संवाददाता-
अंबिकापुर/दरिमा,10 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में पिछले पखवाड़े से जारी प्री-मानसून बारिश के बीच मंगलवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। रात करीब दो बजे तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में भारी नुकसान पहुंचाया। आंधी के कारण गांव में कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। एक विशाल पेड़ बंधन नामक ग्रामीण के मकान पर गिरने से घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय परिवार के सदस्य समय रहते बाहर निकल गए,जिससे जनहानि नहीं हुई। पीड़ित बंधन ने बताया कि मकान के भीतर रखी आलमारी, पेटी,पलंग,बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान मलबे में दब गए हैं। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है।

सड़क पर गिरे पेड़,आवागमन बाधित : मोहनपुर में कई स्थानों पर सड़क पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से आवागमन प्रभावित रहा। बुधवार सुबह सब्जियों से भरा एक ऑटो रिक्शा सड़क किनारे गड्ढे में फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। इधर, अंबिकापुर शहर में भी देर रात करीब एक घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हालांकि शहर में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है और जनजीवन सामान्य बना रहा।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी : नवतपा के दौरान जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था,वहीं लगातार हो रही बारिश के बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। पिछले दिनों तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना जताई है।

370 करोड़ खर्च,बंगले-हॉस्टल बन गए...लेकिन अस्पताल अधूरा

मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट पर भाजपा नेता कैलाश मिश्रा के सवाल

8 साल बाद भी अस्पताल भवन अधूरा,आखिर देरी का जिम्मेदार कौन? सोशल मीडिया वीडियो जारी कर उठाए सवाल...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जून 2026
(घटती-घटना)।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए पूछा है कि आखिर करोड़ों रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अस्पताल भवन का निर्माण वर्षों बाद भी अधूरा क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कैलाश मिश्रा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज परियोजना के लिए लगभग 370 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। परियोजना की मूल प्राथमिकता मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कॉलेज एवं अस्पताल भवन का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत डीन और अधीक्षक के बंगले, ऑडिटोरियम, छात्र-छात्राओं के हॉस्टल तथा कर्मचारियों के विभिन्न आवास पहले तैयार हो गए, जबकि सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल भवन का निर्माण अधूरा रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल भवन का निर्माण पिछले चार वर्षों से बंद पड़ा है और पूरी परियोजना को शुरू हुए करीब आठ वर्ष बीत चुके हैं। उनके अनुसार उस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे टी.एस. सिंहदेव को परियोजना की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर साधा निशाना : श्री मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए टी.एस. सिंहदेव को अस्पताल निर्माण कार्य समय पर पूरा कराने और शेष कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब विधायक नहीं रहने के बाद वे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को राशि उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिख रहे हैं, जबकि यह काम उनके मंत्री रहते होना चाहिए था।

मौजूदा सरकार से भी जवाब मांगा...

भाजपा नेता ने केवल पूर्व सरकार ही नहीं बल्कि वर्तमान व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री राजेश अग्रवाल के कार्यकाल को भी ढाई वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने दावा किया कि 21 जनवरी 2026 को अस्पताल भवन के शेष निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रायपुर की एक कंपनी की लगभग 103.16 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली भी सामने आ चुकी है। इसके बावजूद पांच महीने बाद भी कार्यादेश जारी नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।

अंबिकापुर को मिलना चाहिए आधुनिक अस्पताल

कैलाश मिश्रा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल केवल एक भवन नहीं बल्कि पूरे सरगुजा संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं का आधार है। इसके अधूरा रहने से मरीजों, मेडिकल छात्रों और क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को नुकसान हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अस्पताल भवन निर्माण कार्य शुरू कराएगी ताकि वर्षों से लंबित यह परियोजना पूरी हो सके और अंबिकापुर को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरा समाज : हजारों लोगों ने निकाली रैली,राज्यपाल-सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

- राजमोहनी देवी सेवा संस्थान का नशा मुक्ति अभियान,महिलाओं की रही बड़ी भागीदारी
- बबरू वाहन बोले- माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरुजी ने दिया था मांस-मदिरा त्यागने का संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा को नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ मंगलवार को पद्मश्री माता राजमोहनी देवी सेवा संस्थान के बैनर तले विशाल जनजागरण रैली निकाली गई। शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंची,जहां प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नशा मुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। रैली का नेतृत्व माता राजमोहनी देवी की उत्तराधिकारी पूज्य माता रामबाई तथा संत गहिरा गुरुजी के सुपुत्र और संत गहिरा गुरु सनातन संत आश्रम के अध्यक्ष बबरू वाहन ने किया। इस दौरान जनजाति गौरव समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलखन पैकरा, पूर्व सांसद कमलभान सिंह समेत अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

माता राजमोहनी देवी सभा भवन से शुरू हुई रैली एमजी रोड, अंबेडकर चौक,गांधी चौक और विवेकानंद चौक से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए प्रतिभागी लगातार नशा मुक्ति के नारे लगाते रहे। 'हमर सरगुजा ला नशा ले मुक्त बनाना हे' और 'नशा मुक्ति कर जोर अभियान चलाना हे' जैसे नारों से पूरा मार्ग गूंजता रहा। रैली में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

संतों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास : रैली से पहले सभा भवन में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए बबरू वाहन ने कहा कि माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरुजी ने समाज को मांस एवं मदिरा त्यागकर संयमित जीवन जीने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि आज नशा सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं की बड़ी वजह बन चुका है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसके खिलाफ जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि संतों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही स्वस्थ और संस्कारित समाज का निर्माण संभव है। नशा मुक्ति केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए।

संतों की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर : सभा को संबोधित करते हुए रामलखन सिंह पैकरा ने कहा कि समाज को माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरुजी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उनके विचार आज भी समाज सुधार और जनजागरण के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोगों से संतों के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। पूर्व सांसद कमलभान सिंह ने कहा कि समाज में एकता, जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन के लिए संतों की शिक्षाओं को लगातार स्मरण करते रहना आवश्यक है। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

बड़ी संख्या में शामिल हुए अनुयायी : कार्यक्रम में अमृत सिंह मराबी,त्रिभुवन सिंह, परमेश्वर सिंह मरकाम,अरुणा सिंह,सहदेव भगत,कमला प्रसाद सिंह,धर्म सिंह,संतोष दास,बिहारी लाल उरांव,दिनेश पावेल, कमलेश टोप्पो सहित बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता और माता राजमोहनी देवी के अनुयायी मौजूद रहे। नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई यह रैली शहर में चर्चा का विषय रही और सामाजिक जागरूकता के प्रति लोगों की बढ़ती भागीदारी का संदेश देती नजर आई।

मौसम के उतार-चढ़ाव से बढ़ी मौसमी बीमारियां,शिशु वार्ड के सभी बेड फुल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जून 2026 (घटती-घटना)।

पिछले कुछ दिनों से मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर लोगों की सेहत पर पडने लगा है। कभी तेज गरज-चमक के साथ बारिश तो कुछ ही देर बाद तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई है। इस मौसमीय अस्थिरता के कारण विशेषकर बच्चे सर्दी-खांसी, बुखार और उल्टी-दस्त जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड के सभी बेड भर चुके हैं।

चिकित्सकों के अनुसार बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे मौसमी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चों का उपचार किया जा रहा है और जरूरत पडने पर उन्हें भर्ती भी किया जा रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक इन दिनों जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 350 से 400 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकांश मरीज गर्मी, उमस और मौसम परिवर्तन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जे.के. रेलवानी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग में 60 बेड की व्यवस्था है। पिछले कुछ दिनों से बीमार बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ओपीडी में आने वाले बच्चों में से जरूरतमंद मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जिससे भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग का एक भी बेड खाली नहीं है। यदि मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम भर्ती बच्चों की निगरानी और उपचार में जुटी हुई है।

तापमान में भी हो रहा उतार-चढ़ाव

जून की शुरुआत से ही क्षेत्र में प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं। सुबह और शाम बारिश होने के बाद दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बीते कई दिनों तक अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, लेकिन पिछले दो दिनों में तापमान बढ़कर 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सलाह दी है कि–

- बाहर का खुला और दूषित भोजन खाने से बचें।
- उबला या स्वच्छ पानी ही पिएं।
- भोजन से पहले और नियमित रूप से हाथ धोएं।
- बच्चों को बारिश में भीगने और तेज धूप में अधिक देर तक रहने से बचाएं।
- सर्दी, खांसी, बुखार या उल्टी-दस्त के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
- घर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखें तथा मच्छरों से बचाव के उपाय करें।
- शरीर में पानी की कमी न होने दें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें।

खड़े ट्रक से टकराई कार...युवक की मौत,तेज बारिश के बीच हुआ हादसा,दूसरा युवक घायल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जून 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई,जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसा भिड़ीकला के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार टकराने के कारण हुआ। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमगसी निवासी तेजपाल (19) मंगलवार शाम घर से लखनपुर जाने की बात कहकर

निकला था। रास्ते में उसकी मुलाकात ग्राम नरकालो निवासी दीपक सोनी से हुई। दोनों कार से अंबिकापुर आए थे। रात करीब 2 से 2.30 बजे वे वापस लखनपुर लौट रहे थे। इसी दौरान भिड़ीकला के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक उसमें फंस गए। कुछ देर बाद घायल दीपक किसी तरह बाहर निकल आया और अंबिकापुर पहुंचकर एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया। वहीं तेजपाल कार में बुरी तरह फंसा रहा। हादसे की सूचना मिलते ही मणिपुर थाना प्रभारी सीपी तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उस समय तेज बारिश भी हो रही थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे तेजपाल को बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक आशंका है कि हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी। संभवतः तेज रफ्तार के कारण चालक को सड़क किनारे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और कार सीधे उससे जा भिड़ी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

परमिट एक मार्ग का,संचालन दूसरे मार्ग पर!

आखिर किसके संरक्षण में दौड़ रही हैं बसें?

एमसीबी जिले में निजी बस संचालन पर उठे गंभीर सवाल,नियमों की धज्जियां या जिम्मेदारों की चुप्पी?

-संवाददाता-
एमसीबी,10 जून 2026
(घटती-घटना)।
सड़क परिवहन व्यवस्था किसी भी क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाती है, आम नागरिकों की दैनिक आवाजाही, विद्यार्थियों की पढ़ाई, व्यापारियों का कारोबार और ग्रामीण अंचलों की आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करती हैं,लेकिन जब यही व्यवस्था नियमों से नहीं बल्कि मनमर्जी से संचालित होने लगे,तब सवाल केवल परिवहन सेवाओं पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर उठने लगते हैं। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में इन दिनों निजी बसों के संचालन को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप हैं कि कई निजी बस संचालक जिस मार्ग के लिए परमिट प्राप्त किए हुए हैं,उस मार्ग पर संचालन करने के बजाय दूसरे मार्गों पर बसें चला रहे हैं,इतना ही नहीं,जिन वाहनों के नाम पर परमिट स्वीकृत है, उनकी जगह दूसरे वाहनों के संचालन की चर्चाएं भी क्षेत्र में आम हो चुकी हैं, यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, सरकारी राजस्व और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला है।

परमिट एक बस का, सड़क पर दूसरी बस

मामले का दूसरा और अधिक गंभीर पहलू यह बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर जिस वाहन के नाम पर परमिट जारी है, उसके स्थान पर दूसरी बसों का संचालन किया जा रहा है, यह केवल कागजी अनियमितता नहीं है, किसी वाहन का बीमा, फिटनेस, कर भुगतान, परमिट और सुरक्षा संबंधी सभी दस्तावेज उसी वाहन के लिए मान्य होते हैं, यदि उसकी जगह दूसरा वाहन सड़क पर उतरता है तो दुर्घटना की स्थिति में कानूनी जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं, ऐसी स्थिति में यात्रियों के बीमा दावों, मुआवजे और जिम्मेदारी निर्धारण जैसे मुद्दे भी विवाद का विषय बन सकते हैं।

परमिट की शर्तें आखिर होती क्यों हैं?-

परिवहन विभाग किसी भी वाहन को परमिट जारी करने से पहले उसकी फिटनेस,क्षमता,रूट की आवश्यकता,यात्री भार और अन्य तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करता है,इसके बाद एक निर्धारित मार्ग के लिए अनुमति दी जाती है ताकि उस क्षेत्र के यात्रियों को नियमित और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल सकेलेकिन यदि कोई वाहन स्वीकृत मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर दौड़ने लगे तो फिर परमिट प्रणाली का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है,सवाल यह है कि यदि बस मालिक अपनी सुविधा के अनुसार मार्ग बदलने लगेंगे तो फिर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का औचित्य क्या रह जाएगा?

इन मार्गों को लेकर उठ रहे हैं सवाल

क्षेत्र में चर्चा का विषय बने कुछ मार्गों में मनेंद्रगढ़-उधनापुर-पोड़ी बचरा-प्रेमनगर-बैकुंठपुर-जरौधा तथा बैकुंठपुर-पोड़ी बचरा-चिरमी, प्रेमनगर-खड़गवां-मनेंद्रगढ़ मार्ग शामिल बताए जा रहे हैं,स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बसें अपने स्वीकृत मार्गों पर नियमित संचालन नहीं कर रही हैं, बल्कि अधिक लाभ वाले मार्गों को चुनकर वहां सेवाएं दे रही हैं,परिणाम यह हो रहा है कि जिन क्षेत्रों के लिए परमिट स्वीकृत किए गए थे,वहां के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है जबकि अन्य मार्गों पर बसों की संख्या आवश्यकता से अधिक दिखाई दे रही है, यदि ऐसा हो रहा है तो यह सीधे-सीधे परिवहन नीति और यात्री हितों के विपरीत माना जाएगा।

परिवहन विभाग की भूमिका पर सवाल- सबसे बड़ा प्रश्न परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर खड़ा हो रहा है, यदि बसें वर्षों से दूसरे मार्गों पर संचालित हो रही हैं तो क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? यदि जानकारी नहीं है तो यह विभागीय निगरानी की विफलता मानी जाएगी, और यदि जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्षेत्र में लोग यह चर्चा करते दिखाई देते हैं कि बिना विभागीय जानकारी के इस प्रकार का संचालन लंबे समय तक संभव नहीं हो सकता, यही कारण है कि अब लोगों की उंगलियां केवल बस संचालकों पर ही नहीं बल्कि निगरानी करने वाले तंत्र पर भी उठने लगी हैं।

कहीं प्रतिस्पर्धा खत्म करने का खेल तो नहीं?- कुछ जानकारों का मानना है कि कई बार लाभदायक मार्गों पर कब्जा बनाए रखने के लिए भी इस प्रकार की गतिविधियां सामने आती हैं, यदि किसी बस संचालक को किसी दूसरे मार्ग पर अधिक यात्री और अधिक आमदनी मिल रही है तो वह स्वीकृत मार्ग छोड़कर वहां संचालन शुरू कर देता है, इससे उन बस संचालकों को नुकसान होता है जो नियमों का पालन करते हुए निर्धारित मार्गों पर सेवा दे रहे होते हैं। धीरे-धीरे यह स्थिति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देती है और नियम मानने वाले संचालक आर्थिक नुकसान झेलने लगते हैं।

यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यात्रियों की सुरक्षा का है, जब कोई बस निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित होती है तो उसकी जवाबदेही स्पष्ट रहती है, लेकिन यदि बस, रूट और दस्तावेजों के बीच ही विसंगति हो जाए तो दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है, यात्रियों को यह जानने का अधिकार है कि जिस वाहन में वे सफर कर रहे हैं, वह कानूनी रूप से उसी मार्ग पर संचालित होने के लिए अधिकृत है या नहीं, परिवहन नियम केवल सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

जांच की मांग तेज

क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि जिले में संचालित सभी निजी बसों की विशेष जांच कराई जाए,जांच में निम्न बिंदुओं को शामिल किए जाने की मांग की जा रही है–बस का वास्तविक परमिट किस मार्ग के लिए जारी है,वर्तमान में बस किस मार्ग पर संचालित हो रही है, स्वीकृत वाहन और संचालित वाहन एक ही हैं या नहीं,वाहन की फिटनेस,बीमा और कर संबंधी दस्तावेज अद्यतन हैं या नहीं,निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं, लोगों का कहना है कि जांच केवल औपचारिकता न होकर जमीनी स्तर पर की जानी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

प्रशासन के लिए परीक्षा की घड़ी

यह मामला अब केवल बस संचालन तक सीमित नहीं रह गया है, यह प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के समान अनुपालन का भी प्रश्न बन चुका है,यदि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती तो इससे यह संदेश जाएगा कि व्यवस्था में प्रभावशाली लोगों के लिए अलग नियम हैं और आम लोगों के लिए अलग, दूसरी ओर यदि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाती है तो इससे जनता का विश्वास प्रशासन और परिवहन विभाग दोनों पर मजबूत होगा।

अब जवाब का इंतजार

एमसीबी जिले में परिवहन व्यवस्था को लेकर उठे इन सवालों का जवाब अब प्रशासन और परिवहन विभाग को देना है, क्षेत्र के लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही बसों की जांच होगी, क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी और क्या यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? फिलहाल सड़क पर दौड़ती बसों के साथ-साथ एक सवाल भी दौड़ रहा है–क्या परमिट की शर्तें केवल कागजों तक सीमित हैं, या फिर उनका पालन कराने के लिए भी कोई जिम्मेदार है?

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, सूरजपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 192352 निविदा सूचना क्र. 01/वलेलि / 2026-27. दिनांक 04.06.2026

निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 25.06.2026, (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है -

कार्य का नाम : महान नदी पर गोंदा एनीकट योजना का शेष कार्य ।
अनुमानित लागत : रू. 177.25 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 11.06.2026,समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट : 1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2.निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. 01.08.2010 (संशोधित 22.08.2022)

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, सूरजपुर (छ.ग.)
कृते अधीक्षण अभियंता श्याम बरनई
परियोजना मण्डल, अंबिकापुर,
जिला सरगुजा (छ.ग.)

जी.नं.- 262701258/5

खेत बचाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय कृषक सम्मेलन आयोजित

जैविक खेती को बढ़ावा देने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किसानों से किया आह्वान

-संवाददाता-
खड़गवां,10 जून 2026
(घटती-घटना)।
कृषिविकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,एमसीबी द्वारा 'खेत बचाओ अभियान' के अंतर्गत जैविक खेती मिशन योजनांतर्गत जिला स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन खड़गवां में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में जिलेभर से 300 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, इसके बाद किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक कृषि एवं आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव और जैविक खेती के लाभों से अवगत कराया।

जैविक खेती समय की मांग : मंत्री जायसवाल- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, लेकिन पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, उन्होंने कहा कि बेमौसम पैदा होने वाली सब्जियां और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। ऐसे में जैविक खेती और जैविक खाद को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।

नैनो डीएपी और सनई की खेती पर जोर- मंत्री ने किसानों को नैनो डीएपी के उपयोग की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी एक बोतल लगभग 80 डिसमिल भूमि के लिए पर्याप्त होती है, उन्होंने किसानों से सनई (सन) की खेती अपनाने और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

कृषि महाविद्यालय से मिलने वाले लाभ बताए- स्वास्थ्य मंत्री ने कृषि महाविद्यालयों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान नई तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं तथा लागत कम कर सकते हैं।

300 से अधिक किसान हुए शामिल- सम्मेलन में कृषि स्थायी समिति की सभापति श्रीमती सुनील असमेद सोनवानी, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष रामप्रताप गुप्ता, नगर पंचायत लेदरी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा सहित कई जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं जिलेभर से आए 300 से अधिक किसान उपस्थित रहे, कार्यक्रम के दौरान 'तुहर लाईका, तुहर दुआरी, तुहर कमी श्याम बिहारी' संदेश भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देना रहा।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला सरगुजा , छ0ग0

ईश्तहार

एतत द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पिन्टू कुमार सोनी पिता रामनाथ प्रसाद सोनी उम्र 40 वर्ष निवासी घुटरापारा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 मेरे पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसका घरेलु नाम सुहानी सोनी है वो दर्ज हो गया है जबकी मेरी पुत्री का नाम चिंकी सोनी है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आप्पति हो तो ईस्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक व्यायालय में उपस्थित हाकरे अपना दावा/आप्पति पेश कर सकते है। समय-सीमा के बाद आप्पति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 10/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी।

सील — तहसीलदार ,अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

आगामी तिथि 10/7 / 2026 इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/ विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक राजेश अग्रवाल आ0 स्व. रामनिवास अग्रवाल निवासी पुराना बाजार पारा सूरजपुर, थाना व तहसील सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 2905/2 रकबा क्रमशः 2178 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है। अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था / विभाग को कोई दावा / आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक / लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा / आपत्ति दिनांक 10/7/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 10/6/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका नरेन्द्र कुमार जायसवाल आ0 / पति रामदेव जायसवाल जाति, निवासी डी0सी0 रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - महावीर वार्ड, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1893/4777/1, 1893/4777/7, 1893/4777/17 रकबा 6751.8, 0.02 1/2, 0.04 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/ आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-01.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सुनीता सोनी आ0 / पति शंकर प्रसाद सोनी जाति अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया निवासी नेहरू वार्ड सत्तीपारा है कि मोहल्ला - सत्तीपारा, शीट नम्बर - 2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 665/4 रकबा 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः 01.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

NOTICE

It is inform to the general public that I Nazneen daughter of late Md. Sharit was an original resident of Bilaspur, Chhattisgarh, and my primary education took place in Bilaspur, At that time, my name was recorded solely as Nazneen in my educational certificates. In the year 1981, I was duly married according to Muslim customs and traditions to Md, Zahid Khan, son of late Zarif khan, resident of Ambikapur city, Police station and Tehsil Ambikapur, district sarguja, Chhattisgarh, After 1981 I started writing my husbands surname Khan after my name, but in official government document, my name remainded displayed only as Nazneen When I obtained my Aadhar card, Voter ID Card, and PAN Card, My name was recorder in those documents as Nazneen Khan, wife of Md. Zahid Khan, resident of Resulpur, ward no. 39 house no.15,

There fore from today onwards, I should be known and recogined in all government semi government and other documents by my new name Nazneen Khan, wife of Md, Zahid Khan along with Nazneen.

Applicant
Nazneen Khan
W/O Md, Zahid Khan
Resident of Rasulpur
Ambikapur
District Sarguja Chhattisgarh

निधन

स्व0 भगवानदास झा

अंबिकापुर,10 जून 2026 (घटती-घटना)। नमनाकला शनि धाम निवासी वरिष्ठ समाजसेवी एवं सम्मानित नागरिक स्वर्गीय भगवानदास झा (72 वर्ष) का 9 जून 2026 को हृदयाघात के चलते आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही नमनाकला सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। स्वर्गीय झा अपने पीछे पत्नी, पुत्र राजेश झा एवं राजू झा, पुत्रियां रिंकू तिवारी एवं पिंकी झा, पौत्र वंश और अंश सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अपने सौम्य स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकारों के कारण वे क्षेत्र में विशेष पहचान रखते थे। उनके निधन से परिवार के साथ-साथ समाज ने भी एक सम्मानित एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व को खो दिया है। बुधवार सुबह उनकी अंतिम यात्रा नमनाकला स्थित निवास से शंकर घाट मुक्तिधाम के लिए निकाली गई। अंतिम यात्रा में परिजन, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतक तथा क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। शंकर घाट मुक्तिधाम में वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। स्वर्गीय भगवानदास झा के निधन पर सामाजिक, धार्मिक एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित क्षेत्रवासियों ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

जिम्मेदारी छुट्टी पर,संरक्षण ड्यूटी पर !

कोरिया कलेक्ट्रेट में आखिर किसका चलता है असली सिस्टम?

- कोरिया के स्थायी स्टेनो राज से उठता बड़ा सवाल,फाइलों का लोकतंत्र या संरक्षण का साम्राज्य?
- शिकायतें दौड़ती रहीं,खबरें छपती रहीं...लेकिन कार्रवाई शायद रास्ता भूल गई!
- कलेक्टर बदले,सिस्टम नहीं! कोरिया के 'स्थायी स्टेनो राज' पर फिर उठे बड़े सवाल...
- नियम अलग...व्यवस्था अलग...कोरिया कलेक्ट्रेट में प्रतिनियुक्ति का ऐसा जलवा कि सवाल भी फाइलों में कैद!
- फाइलें बोल नहीं रहीं,सवाल बढ़ते जा रहे हैं,कोरिया के चर्चित स्टेनो प्रकरण पर प्रशासन की चुप्पी क्यों?
- कलेक्टर साहिबा नई,लेकिन सिस्टम पुराना! स्थायी स्टेनो राज पर जवाबदेही होगी या संरक्षण जारी रहेगा?
- हम नहीं बदलते...कलेक्टर बदलते रहते हैं! कोरिया कलेक्ट्रेट में 'स्थायी स्टेनो मॉडल' पर उठ रहे गंभीर सवाल...
- संरक्षण मॉडल बनाम जवाबदेही मॉडल,कोरिया कलेक्ट्रेट का चर्चित स्टेनो प्रकरण अब आयुक्त कार्यालय तक पहुंचा
- फाइलों में दबे सवाल,कुर्सी पर कायम प्रभाव स्थायी स्टेनो राज की परतें कब खोलेगा प्रशासन?
- कोरिया कलेक्ट्रेट में कौन चला रहा है असली सिस्टम? कलेक्टर बदलते रहे,लेकिन 'स्थायी स्टेनो राज' क्यों नहीं बदला?

जब खबरें थक गईं,लेकिन व्यवस्था नहीं जागी...

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य व्यवस्था को आईना दिखाना होता है,कोरिया में यह आईना पिछले कई महीनों से लगातार एक ही तस्वीर दिखा रहा है, नियुक्ति पर सवाल,पदोन्नति पर सवाल,प्रतिनियुक्ति पर सवाल,सर्विस बुक पर सवाल,आरटीआई पर सवाल,शिकायतों पर सवाल,लेकिन हैरानी की बात यह है कि सवालों की संख्या बढ़ती गई और जवाबों की संख्या घटती गई,स्थिति ऐसी हो गई है मानो खबरें अखबार में नहीं बल्कि किसी सरकारी फाइल के खाली पन्नों पर छप रही हों,जिन्हें पढ़ने की किसी को जल्दी ही नहीं है,जनता पूछ रही है कि यदि आरोप गलत हैं तो उनका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा? और यदि आरोपों में दम है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन जवाब देने की जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसा सन्नाटा, जिसमें केवल फाइलों के पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती है,निर्णय लेने की नहीं।

छह महीने में पदोन्नति,सरकारी सेवा या प्रशासनिक रॉकेट विज्ञान?

सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारी इस खबर को पढ़कर शायद अपने माथे पर हाथ रख लें,दस्तावेज बताते हैं कि संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति 7 अप्रैल 1986 को स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर हुई और महज छह महीने बाद 27 अक्टूबर 1986 को स्टेनोग्राफर बना दिए गए,अब यह सूचना उन कर्मचारियों को न बताइए जो 10-15 वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं,वरना वे इसे प्रशासनिक चमत्कार घोषित कर सकते हैं,सरकारी कार्यालयों में सामान्यतः पदोन्नति की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कई बार कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यहां यदि वास्तव में छह महीने में पद परिवर्तन हुआ है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? क्या उस समय नियम कुछ और थे? क्या कोई विशेष प्रावधान था? या फिर यह ऐसा प्रशासनिक करिश्मा था जिसकी जानकारी बाकी कर्मचारियों को कभी नहीं मिल सकी? जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि जवाब जितना देर से मिलेगा,संदेह उतना गहरा होगा।

मत्स्य निगम विभाग का कर्मचारी,राजस्व विभाग का प्रभाव!

पूरे प्रकरण का सबसे दिलचस्प अध्याय प्रतिनियुक्ति का है,जानकारी के अनुसार संबंधित कर्मचारी मूलतः मत्स्य विभाग से जुड़े बताए जाते हैं, लेकिन वर्षों से राजस्व विभाग और कलेक्ट्रेट में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं,अब सवाल यह नहीं है कि प्रतिनियुक्ति हुई या नहीं,सवाल यह है कि प्रतिनियुक्ति कितने समय के लिए हुई थी? क्या उसका नवीनीकरण होता रहा? यदि हुआ तो किस आधार पर? और यदि नहीं हुआ तो फिर यह व्यवस्था आखिर चली कैसे? सरकारी तंत्र में प्रतिनियुक्ति आम बात है,लेकिन जब प्रतिनियुक्ति दशकों तक चलने लगे तो लोग उसे प्रतिनियुक्ति नहीं, स्थायी साम्राज्य मानने लगते हैं,यही कारण है कि कलेक्ट्रेट के गलियारों में लोग अब मजाक में कहने लगे हैं कि सरकारें अस्थायी हो सकती हैं,लेकिन कुछ प्रतिनियुक्तियां स्थायी होती हैं।

सर्विस बुक : प्रशासन की गुमशुदा डायरी?

किसी भी सरकारी कर्मचारी की सर्विस बुक उसकी आधिकारिक जीवनी होती है,उसमें नियुक्ति से लेकर पदोन्नति,वेतनवृद्धि,अवकाश,स्थानांतरण और सेवा संबंधी हर महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज रहती है,लेकिन जब किसी कर्मचारी की सर्विस बुक को लेकर ही रहस्य पैदा हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है,कोरिया में आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि संबंधित कर्मचारी की सर्विस बुक आखिर है कहां? मत्स्य विभाग में? राजस्व विभाग में? किसी रिकॉर्ड रूम में? या फिर वह भी उन फाइलों के साथ गुमशुदा है जिनकी चर्चा वर्षों से होती रही है? यह सवाल केवल दस्तावेज का नहीं बल्कि पारदर्शिता का है, यदि रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो उन्हें सामने रखने में परेशानी क्या है?

अब आयुक्त कार्यालय भी कटघरे में...

पहले सवाल कलेक्ट्रेट तक सीमित थे,लेकिन अब सवाल संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंच गए हैं,कारण साफ है,जब जिला स्तर पर जवाब नहीं मिलता तो लोग उच्च स्तर की ओर देखते हैं,यदि वहां भी चुप्पी दिखाई दे तो लोगों को लगता है कि शायद मामला सामान्य नहीं है,आयुक्त कार्यालय प्रशासनिक निगरानी का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है,ऐसे में यदि लगातार सवाल उठ रहे हों और कोई स्पष्ट स्थिति सामने न आए तो स्वाभाविक रूप से संदेह बढ़ता है,यही कारण है कि अब लोगों की नजरें संभागीय स्तर पर टिकी हुई हैं।

-रवि सिंह-

कोरिया,10 जून 2026 (घटती-घटना)।

लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं,अधिकारी बदलते हैं, कलेक्टर बदलते हैं,आयुक्त बदलते हैं,बाबू बदलते हैं,फाइलों के रंग बदल जाते हैं,लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो किसी पुराने बरगद की तरह जड़ें जमा लेती हैं,समय गुजरता रहता है,शासन बदलता रहता है,नीतियां बदलती रहती हैं,मगर वे व्यवस्थाएं अपनी जगह अडिग खड़ी रहती हैं। कोरिया जिले में इन दिनों एक ऐसा ही सवाल प्रशासनिक गलियारों से निकलकर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है,सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जिसे लोग अब व्यंग्य में संरक्षण मॉडल कहने लगे हैं,लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब शासन का नया सिद्धांत यही है कि जिम्मेदारी बाद में देखी जाएगी और संरक्षण पहले दिया जाएगा? क्या अब नियमों की किताब केवल कमजोर कर्मचारियों के लिए बची है और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग संविधान लागू हो चुका है? इन सवालों की वजह है कोरिया कलेक्ट्रेट में वर्षों से चर्चा में बना तथाकथित स्थायी स्टेनो प्रकरण,जो अब केवल कलेक्ट्रेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि संभागीय आयुक्त कार्यालय की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

आरटीआई बनाम फाइलों का किला...

सूचना का अधिकार कानून इसलिए बनाया गया था ताकि जनता को सरकारी सूचनाएं आसानी से मिल सकें,लेकिन यदि सूचना मांगने के बाद भी स्पष्ट जानकारी न मिले तो जनता के मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है,सूत्रों के अनुसार इस मामले में कई बार आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन अपेक्षित सूचनाएं नहीं मिल सकीं,यह स्थिति लोगों को और अधिक सोचने पर मजबूर कर रही है,क्योंकि जब सूचना मांगने वाला जवाब न पाए तो उसे लगता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं,और जब दीवारें ज्यादा ऊंची हो जाती हैं तो लोग उन्हें संरक्षण का किला मानने लगते हैं।

शिकायतों का अंतिम संस्कार कहां होता है?

यह प्रश्न आज कोरिया जिले में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वर्षों में हुई शिकायतों का क्या हुआ? वे किस अधिकारी तक पहुंचीं? उनकी जांच हुई या नहीं? उनका निष्कर्ष क्या रहा? इन सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं,इसी वजह से कर्मचारियों के बीच व्यंग्य चल पड़ा है कि कुछ शिकायतें जांच अधिकारी तक पहुंचती हैं और कुछ शिकायतें सीधे इतिहास विभाग में भेज दी जाती हैं, कई कर्मचारी मजाक में कहते हैं कि यदि शिकायत किसी सामान्य कर्मचारी के खिलाफ हो तो नोटिस डाक से पहले पहुंच जाता है, लेकिन यदि मामला प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हो तो फाइल पहले सोचती है,फिर रुकती है और फिर लंबी नींद में चली जाती है।

हर नए कलेक्टर से नई शुरुआत,लेकिन वही पुराना प्रभाव?

प्रशासनिक गलियारों में एक और चर्चा लंबे समय से सुनाई देती रही है, कहा जाता है कि जिले में आने वाले लगभग हर नए कलेक्टर के साथ संबंधित कर्मचारी ने बेहतर कार्य संबंध स्थापित किए, हालांकि इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन कर्मचारियों के बीच यह धारणा लगातार बनी हुई है, यही वजह है कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वह कौन-सी कार्यकुशलता है जो दशकों तक प्रभाव बनाए रखने में सफल रही? क्या यह केवल अनुभव का परिणाम है? या फिर सिस्टम को समझने और संचालित करने की विशेष कला? जो भी हो,इस चर्चा ने पूरे प्रशासनिक ढांचे पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

संरक्षण मॉडलः लोकतंत्र का नया प्रयोग?

यदि जनता की नजर से देखा जाए तो आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या शासन का केंद्र अब जवाबदेही है या संरक्षण? क्या नियम सबके लिए समान हैं? क्या प्रभावशाली और सामान्य कर्मचारी के लिए एक जैसी प्रक्रिया लागू होती है? यदि हां, तो फिर कार्रवाई में यह अंतर क्यों दिखाई देता है? यदि नहीं,तो फिर व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास होता है, और जब लोगों को लगने लगे कि नियमों का उपयोग चयनात्मक तरीके से हो रहा है, तब विश्वास कमजोर होने लगता है।

जवाबदेही की घड़ी कब बजेगी?

पूरा मामला आखिरकार कुछ सीधे सवालों पर आकर रुक जाता है,क्या नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होगी? क्या प्रतिनियुक्ति के दस्तावेज सार्वजनिक होंगे? क्या सर्विस बुक की स्थिति स्पष्ट की जाएगी? क्या आरटीआई से जुड़े सवालों का समाधान होगा? क्या वर्षों की शिकायतों का सत्यापन किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण– क्या प्रशासन यह साबित करेगा कि उसके लिए जिम्मेदारी मॉडल अभी भी जीवित है? या फिर जनता यह मान ले कि संरक्षण मॉडल ही नया प्रशासनिक दर्शन बन चुका है? फिलहाल कोरिया की फाइलें खामोश हैं, अधिकारी मौन हैं और सवाल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि फाइलें चाहे जितनी देर तक बंद रहें, एक दिन खुलती जरूर हैं, और जब वे खुलती हैं तो केवल कागज नहीं बोलते, पूरी व्यवस्था की कहानी सामने आ जाती है,आज कोरिया में चर्चा किसी एक स्टेनो की नहीं है। चर्चा उस तंत्र की है जिसमें लोग यह जानना चाहते हैं कि शासन की असली ताकत नियम हैं या रिश्ते,जवाबदेही है या संरक्षण,और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता,तब तक यह प्रकरण प्रशासनिक गलियारों में गूंजता रहेगा–एक ऐसे सवाल की तरह,जिसका जवाब फाइलों में कहीं दबा हुआ बताया जाता है।

C M Y K

विशेष रिपोर्ट

जिला तो बन गया साहब, पर सड़कें अब भी गली ही हैं!

मनेन्द्रगढ़ की अधूरी विकास गाथा

- जिला बनने का सपना पूरा, लेकिन चौड़ी सड़कों का सपना अब भी फाइलों में कैद
- मेडिकल कॉलेज आया, जिला बना, दफ्तर बढ़े... मगर सड़कें क्यों नहीं बढ़ीं?
- मनेन्द्रगढ़ पूछ रहा है– साहब, जिला बनने के बाद क्या सड़कों की बारी नहीं आती?
- विकास की गाड़ी फंस गई जाम में! जिला बनने के बाद भी संकरी सड़कों से जूझता मनेन्द्रगढ़

-रवि सिंह-

मनेन्द्रगढ़, 10 जून 2026 (घटती-घटना)।

मनेन्द्रगढ़ की कहानी किसी साधारण नगर की कहानी नहीं है, यह उस शहर की कहानी है जिसने जिला बनने का सपना देखा, उसके लिए दशकों तक संघर्ष किया,नेताओं के भाषण सुने,आश्वासन की मिठाइयाँ खाई, चुनावी घोषणाओं की चाशनी में डूबा रहा और आखिरकार जिला बन भी गया,लेकिन आज जब कोई आम नागरिक बाजार की सड़क पर फंसकर आधे घंटे तक जाम में खड़ा रहता है तो उसके मन में एक ही सवाल उठता है,क्या जिला बनने का मतलब सिर्फ नाम बदलना था या व्यवस्था भी बदलनी थी? कभी सरगुजा जिले का हिस्सा रहे मनेन्द्रगढ़ ने सबसे पहले जिला बनने का सपना देखा था,उस दौर में जब अविभाजित मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी,तब यहां के लोग लगातार यह मांग उठा रहे थे कि मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाया जाए,उस समय शहर में रेलवे स्टेशन था,व्यापारिक गतिविधियां थीं,प्रशासनिक दृष्टि से संभावनाएं थीं और भौगोलिक रूप से भी यह एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था,लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, वर्ष 1998 आया, सरगुजा का विभाजन हुआ, कोरिया जिला बना,लोगों को उम्मीद थी कि मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय बनेगा, लेकिन अंतिम समय में बाजी किसी और के हाथ चली गई,मनेन्द्रगढ़ देखते रह गया और जिला मुख्यालय का ताज बैकुंठपुर के सिर पर सज गया,उस दिन से लेकर वर्षों तक मनेन्द्रगढ़ के हिस्से में सिर्फ इंतजार आया।

मनेन्द्रगढ़ के बुजुर्ग बताते हैं कि उस दौर में यदि दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व और सुनियोजित शहरी सोच दिखाई गई होती तो आज शहर की तस्वीर कुछ और होती,लेकिन हुआ उल्टा, जिस समय शहर को भविष्य के लिए तैयार किया जाना चाहिए था,उसी समय सरकारी भूमि धीरे-धीरे सिकुड़ती चली गई, सड़कों के किनारे अतिक्रमण बढ़ता गया,शहर का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ,आज स्थिति यह है कि शहर का मुख्य बाजार ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी पुराने दौर की तंग गलियों को आधुनिक जिला मुख्यालय घोषित कर दिया गया हो,व्यंग्य की बात यह है कि जिला बनने के लिए जिस शहर ने दशकों तक संघर्ष किया, वह जिला बनने के बाद भी कई जगहों पर कस्बे जैसी यातायात व्यवस्था से जूझ रहा है।

सब जानते हैं समस्या क्या है,लेकिन बोलता कौन है ?

सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इस विषय पर बड़े स्तर पर कोई जनआंदोलन दिखाई नहीं देता, व्यापारिक संगठन चुप,सामाजिक संगठन शांत, जनप्रतिनिधि व्यस्त,नागरिक परेशान,और सड़कें मौन,मानो पूरे शहर ने यह मान लिया हो कि जाम मनेन्द्रगढ़ की नियति है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन शहरों ने अपनी बुनियादी समस्याओं को समय रहते नहीं सुलझाया,वहां विकास की गति अंततः रुक जाती है।

जिला मुख्यालय का दर्जा केवल बोर्ड पर नहीं दिखना चाहिए...

किसी भी शहर को जिला घोषित करना प्रशासनिक निर्णय होता है,लेकिन जिला मुख्यालय जैसी पहचान केवल सरकारी अधिसूचना से नहीं बनती,उसके लिए चाहिए–चौड़ी सड़कें,सुव्यवस्थित यातायात,पार्किंग व्यवस्था,अतिक्रमण मुक्त मार्ग,सुरक्षित पैदल रास्ते,और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई विकास योजना,यदि ये सब नहीं हैं तो जिला मुख्यालय का दर्जा केवल बोर्ड और दस्तावेजों में दिखाई देता है,जमीन पर नहीं।

अंतिम सवालः जिला बनने का जश्न कब तक ?

मनेन्द्रगढ़ ने जिला बनने का सपना देखा था,वह सपना पूरा हो गया,लेकिन आज एक नया सपना शहर की आंखों में दिखाई देता है, वह सपना है ऐसी सड़कों का जिन पर एम्बुलेंस बिना रुके निकल सके, ऐसे बाजार का जहां ग्राहक परेशान न हो,ऐसी यातायात व्यवस्था का जहां जाम अपवाद हो,नियम नहीं, और ऐसे विकास का जिसमें जिला मुख्यालय की पहचान केवल नाम में नहीं बल्कि व्यवस्था में भी दिखाई दे,आज मनेन्द्रगढ़ के लोग फिर एक सवाल पूछ रहे हैं–साहब,जिला बनने का जश्न तो हम मना चुके...अब बताइए,सड़कें कब चौड़ी होंगी? क्योंकि शहर का धैर्य अब जवाब मांग रहा है,और विकास की असली परीक्षा किसी भवन के उद्घाटन में नहीं,बल्कि उस सड़क पर होती है जिस पर आम नागरिक रोज चलता है। मनेन्द्रगढ़ की सड़कें आज भी उसी जवाब का इंतजार कर रही हैं।

व्यापारी भी खुश, ग्राहक भी परेशान...

मनेन्द्रगढ़ के बाजार की सबसे दिलचस्प तस्वीर यह है कि यहां हर कोई समस्या से परेशान है, लेकिन समाधान पर सहमति नहीं है,व्यापारी चाहते हैं कि ग्राहक आएं,ग्राहक चाहते हैं कि आसानी से पहुंच सकें,वाहन चालक चाहते हैं कि पार्किंग मिले,पैदल चलने वाले चाहते हैं कि रास्ता मिले, लेकिन जब सड़क चौड़ीकरण की बात आती है तो सब अपने-अपने हिस्से की सुविधा बचाने में लग जाते हैं,यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रोज शिकायत करे कि घर में जगह कम है,लेकिन दीवार हटाने की बात आते ही विरोध करने लगे।

मनेन्द्रगढ़ का असली संघर्ष अब शुरू हुआ है...

जिला बनना मंजिल नहीं था,वह तो केवल पहला पड़ाव था,असली चुनौती अब शुरू हुई है,अब यह तय करना होगा कि मनेन्द्रगढ़ आने वाले 20 वर्षों का शहर बनेगा या पिछले 20 वर्षों की गलतियों को ढोता रहेगा,अब यह तय करना होगा कि विकास का मतलब केवल भवन निर्माण होगा या नागरिक सुविधाएं भी होंगी,अब यह तय करना होगा कि अतिक्रमण और अव्यवस्था को नियति मान लिया जाएगा या उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

जाम : शहर का नया स्थायी निवासी

मनेन्द्रगढ़ में यदि किसी चीज ने सबसे स्थायी रूप से निवास कर लिया है तो वह है जाम,सुबह स्कूल का समय,दोपहर बाजार का समय,शाम खरीदारी का समय,हर समय जाम मौजूद रहता है,ऐसा लगता है जैसे शहर का सबसे नियमित नागरिक अब ट्रैफिक जाम ही बन चुका है,लोगों ने भी इसे जीवन का हिस्सा मान लिया है,कोई हॉर्न बजाता है,कोई बाइक घुमाता है,कोई गाड़ी छोड़कर पैदल निकल जाता है,और प्रशासन समय-समय पर व्यवस्था सुधारने की कोशिश करता है,लेकिन समस्या की जड़ वहीं रहती है–संकरी सड़कें और बढ़ता दबाव।

22 साल बाद आया अवसर,लेकिन कहानी में नया मोड़ भी आया...

1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना,लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद मनेन्द्रगढ़ की किस्मत बदलेगी,लेकिन फिर भी वर्षों तक कुछ नहीं हुआ,अंततः 9 सितंबर 2022 को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला अस्तित्व में आया, शहर में उत्साह था, पटाखे फूटे, मिठाइयां बंटी,बधाइयां दी गईं,लेकिन कुछ लोगों ने उसी समय एक सवाल भी पूछा था—जिला तो बन गया,लेकिन क्या शहर जिला मुख्यालय बनने के लिए तैयार है? आज वही सवाल और बड़ा होकर सामने खड़ा दिखाई देता है।

जिले के नाम में पहला स्थान,विकास की दौड़ में आखिरी चिंता ?

मनेन्द्रगढ़ जिले के नाम में सबसे पहले आता है,जिला मुख्यालय भी यहीं है,लेकिन आम नागरिकों के बीच अक्सर यह चर्चा सुनाई देती है कि जिले के नाम में भले ही मनेन्द्रगढ़ सबसे आगे हो,लेकिन विकास की चर्चा आते ही वह कहीं पीछे छूट जाता है, यह धारणा सही है या गलत,इसका फैसला जनता करेगी,लेकिन इतना जरूर है कि शहर के भीतर मौजूद समस्याएं इस भावना को जन्म देती हैं,यदि कोई जिला मुख्यालय बनने के बाद भी जाम,अतिक्रमण और संकरी सड़कों की समस्या से जूझ रहा हो,तो स्वाभाविक है कि लोग सवाल पूछेंगे।

मेडिकल कॉलेज आ गया,लेकिन मरीज जाम में फंस गए...

आज मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है,यह निस्संदेह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विकास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम इमारतों पर चर्चा करते हैं,रास्तों पर नहीं,अस्पताल बनेंगे,कॉलेज बनेंगे,कार्यालय बढ़ेंगे,जनसंख्या बढ़ेगी, वाहन बढ़ेंगे,लेकिन क्या सड़कें भी बढ़ेंगी? यही वह सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं दिखाई देता,यदि एक मरीज को अस्पताल पहुंचने के लिए जाम में फंसना पड़े तो मेडिकल कॉलेज का महत्व कम नहीं होता,लेकिन व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं।

पीडब्ल्यूडी तिराहा से स्टेशन रोड तक : विकास का सबसे बड़ा आईना...

यदि कोई मनेन्द्रगढ़ की वास्तविक स्थिति समझना चाहता है तो उसे पीडब्ल्यूडी तिराहा से स्टेशन रोड तक का सफर करना चाहिए,यह सड़क केवल सड़क नहीं है,बल्कि शहर की योजना,प्रशासनिक इच्छाशक्ति और विकास की प्राथमिकताओं का आईना है,जहां कभी भविष्य के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जा सकती थी,वहां आज अतिक्रमण, अव्यवस्था और भीड़ का दबाव दिखाई देता है,हर चुनाव में विकास की बातें होती हैं, हर मंच पर शहर को आगे बढ़ाने की बातें होती हैं,लेकिन सड़कें वहीं की वहीं हैं,ऐसा लगता है जैसे सड़कों ने भी यह तय कर लिया हो कि जब तक राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी,हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे।

हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला

मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास,साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले को 3 वर्ष की कठोर सजा,पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या कर शव को बोरे में भरकर बांध में फेंका था,लगभग पांच साल बाद आया फैसला...

शव की पहचान ने जांच को नई दिशा दी...

विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान सुरेन्द्र यादव पिता हीरासाय यादव, उम्र 22 वर्ष,निवासी हनुमानगढ़,थाना रामानुजनगर के रूप में की,पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण हत्यात्मक बताया, रिपोर्ट प्राप्त होते ही थाना प्रेमनगर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपराध दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई।

दीदी-जीजा के घर जाने के बाद हुआ था लापता...

जांच में सामने आया कि 5 सितम्बर 2021 को सुरेन्द्र यादव अपनी बहन और जीजा के घर अम्बिकापुर गया था,वहां से वह अपने जीजा सुखसाय उर्फ गंवटिया बरगाह के साथ उसके पुत्र को लेने विध्यांचल गया था, अगले दिन सुखसाय अपने पुत्र के साथ वापस लौट आया,लेकिन सुरेन्द्र उसके साथ नहीं था,जब परिवार के लोगों ने सुरेन्द्र के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि वह प्रेमनगर में उतरकर अपने घर चला गया है,यहीं से पुलिस का शक गहराया और पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया।

मेडिकल दस्तावेज फाड़ने को लेकर हुआ विवाद...

पुलिस पूछताछ में जो तथ्य सामने आए,वे चौंकाने वाले थे,विवेचना के अनुसार विध्यांचल स्थित मकान में 5 सितम्बर की रात सुरेन्द्र यादव और आरोपी सुखसाय के बीच मृतक के पिता के मेडिकल दस्तावेज फाड़ देने की बात को लेकर विवाद हुआ,विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में लकड़ी की पराठी उठाकर सुरेन्द्र के सिर पर हमला कर दिया,गंभीर चोट लगने के बाद आरोपी ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद रची गई साक्ष्य मिटाने की साजिश...

हत्या के बाद आरोपी ने अपराध को छिपाने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची, पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के शव को बोरे में भरकर साइकिल में रखा गया,इसके बाद आरोपी सुखसाय ने अपने पिता महावीर बरगाह की मदद से शव और साइकिल को छोटे छुरी बांध के डुबान क्षेत्र में ले जाकर पत्थर बांधकर पानी में फेंक दिया ताकि शव की पहचान न हो सके और अपराध के साक्ष्य नष्ट हो जाएं,लेकिन अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो,परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पुलिस की जांच ने आखिरकार पूरे मामले का खुलासा कर दिया।

-संवाददाता-

सूरजपुर, 10 जून 2026 (घटती-घटना)।

बहुचर्चित सुरेन्द्र यादव हत्याकांड में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास तथा साक्ष्य छिपाने में सहयोग करने वाले सहआरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है,न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों,गवाहों के बयान और विवेचना के दौरान संकलित तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध माना,यह मामला वर्ष 2021 का है, जिसने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी,एक युवक का शव बांगों बांध के डुबान क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद शुरू हुई जांच ने एक ऐसी कहानी उजागर की थी,जिसमें रिश्तों का भरोसा, क्रोध और अपराध की साजिश एक साथ सामने आई। 11 सितम्बर 2021 को ग्राम बलदेवनगर निवासी मनोज उरांव ने थाना प्रेमनगर में सूचना दी कि बांगों बांध के डुबान क्षेत्र छोटे छुरी में पानी के ऊपर किसी व्यक्ति का पैर दिखाई दे रहा है, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पानी में फंसे शव को बाहर निकाला गया,शव के गले में रस्सी बंधी हुई थी,जिससे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ,पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस विवेचना बनी मामले की सबसे मजबूत कड़ी...

मामले के विवेचक उपनिरीक्षक निर्मल राजवाड़े ने घटनास्थल निरीक्षण, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी तथ्यों को संकलित करते हुए मजबूत आरोप पत्र तैयार किया,पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष ने रखे मजबूत तर्क...

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह कुशवाहा ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए,अभियोजन ने यह साबित करने का प्रयास किया कि आरोपी सुखसाय ने जानबूझकर सुरेन्द्र यादव की हत्या की और बाद में अपने पिता महावीर की सहायता से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया,न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को दोषी पाया।

न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह की अदालत ने 5 जून 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सुखसाय उर्फ गंवटिया को हत्या का दोषी करार दिया,न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई,साथ ही धारा 201/34 के तहत साक्ष्य मिटाने के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया,वहीं सहआरोपी महावीर बरगाह को धारा 201/34 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

न्याय का संदेश...

इस फैसले को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हत्या जैसे जघन्य अपराध और उसके बाद साक्ष्य छिपाने की कोशिश करने वालों को कानून किसी भी स्थिति में राहत नहीं देता,करीब पांच वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस निर्णय ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज को यह संदेश भी दिया है कि अपराध चाहे जितनी चतुराई से छिपाने का प्रयास किया जाए,कानून की पकड़ से बच पाना आसान नहीं होता।

CMYK

धमाल 4 : खजाने के खोज में निकले अजय देवगन

सुपरस्टार अजय देवगन की अपकमिंग मल्टी स्टारर फिल्म धमाल 4 की नई रिलीज डेट को लेकर लेटेस्ट सामने आ रहा है।लंबे समय से अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म धमाल 4 का नाम चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों से फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर्स और जरूर अपडेट्स सामने आ रहे हैं। मंगलवार को मेकर्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि जल्द ही कुछ नया सरप्राइज दिए जाएंगे, जो अब सामने आ गया है।
धमाल 4 के ये सरप्राइज फिल्म की नई रिलीज डेट और ट्रेलर रिलीज को लेकर है। आइए जानते हैं कि अजय की ये मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी बड़े पर्दे पर कब दस्तक देगी और इसका ट्रेलर कब सामने आएगा।

कब रिलीज होगा धमाल 4 का ट्रेलर

अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म के तौर पर धमाल 4 का नाम काफी समय से सुर्खियां बटोर रहा है। अब उनकी ये मूवी पूरी तरह से ऑडियंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की तरफ से धमाल 4 की नई रिलीज डेट और ट्रेलर रिलीज को लेकर अहम जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है। जिसके आधार पर धमाल 4 का ट्रेलर 12 जून को रिलीज किया जाएगा। साथ ही फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर में पूरी कास्ट नजर आ रही है, जिसे देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अजय देवगन एंड कंपनी इस बार जंगल में खजाने की खोज में निकलेगी, जहां उनको एंडवेंचर का सामना करना पड़ेगा और ऑडियंस का ठहाके लगाने का मौका मिलेगा।
इसके साथ ही धमाल 4 की नई रिलीज डेट को भी रिवील किया गया है, जिसके तहत अगले महीने 10 जुलाई को अजय देवगन की इस अपकमिंग कॉमेडी फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि पहले ये मूवी 17 जुलाई को रिलीज होने वाली थी।

धमाल 4 की कास्ट

निर्देशक इंदर कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली धमाल 4 की कास्ट हमेशा की तरह काफी लंबी है। इस बार आपको इस कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजीदा शेख, संजय मिश्रा, उपेंद्र लियमे, अंजलि धवन और रवि किशन जैसे कई कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

13 साल की उम्र में करीना कपूर को हुआ था पहला प्यार

करीना कपूर बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिनकी निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है। उन्होंने साल 2012 में अभिनेता सैफ अली खान से शादी की थी और उससे पहले उनका नाम अभिनेता शाहिद कपूर के साथ भी जुड़ चुका है। लेकिन इन रिश्तों से पहले भी करीना की जिंदगी में एक ऐसा नाम था, जिसे उन्होंने अपना पहला प्यार बताया था। करीना कपूर खान ने एक पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वह सिर्फ 13 साल की थीं, तब उन्हें पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। यह वह उम्र थी जब वह स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं और फिल्मी दुनिया से अभी दूर थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात और आकर्षण एक ऐसे शख्स की ओर हुआ, जिसे उन्होंने बाद में अपना पहला प्यार और सोलमेट तक बताया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि दिवंगत फिल्ममेकर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी के बेटे विक्की निहलानी थे। करीना ने बताया था कि उस समय यह भावना बेहद मासूम थी और वह उम्र के हिसाब से किसी गंभीर रिश्ते को समझने की स्थिति में नहीं थीं। बावजूद इसके, उस आकर्षण ने उनके बचपन की यादों में एक खास जगह बना ली।

पुलिस ने डंडे मारे...खाना तक मांगना पड़ा...नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद मिथुन चक्रवर्ती हुए थे पैसों के मोहताज

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह ने हाल ही में बताया कि उनके पिता की जिंदगी में एक समय ऐसा था,जब उन्होंने पैसों की तंगी की वजह से खाना भी मांगकर खाया था।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्हें बॉलीवुड का डिस्को डांसर भी कहा जाता है। यह इमेजिन करना थो ा मुश्किल हो सकता है कि राष्ट्रीय सम्मान पाने के बाद भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दूसरों से मांग के खाना खाने की नौबत आई होगी।
हालांकि,ऐसा हुआ है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं,बल्कि उन्हीं के ही बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने किया है। अभिनेता ने बताया कि शुरूआती करियर में उनके पिता मिथुन दा को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

रात में पार्क में सोया करते थे मिथुन चक्रवर्ती

मिमोह चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ कनन को दिए गए इंटरव्यू में अपने पिता के संघर्ष के बारे में बातचीत करते हुए कहा,पापा के स्ट्रगल की कहानी मुझे अंदर से झकझोर देती है। वह मुझे बताया करते थे कि कैसे उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा था, जब वह पार्क में सोया करते थे और पुलिसवाला आता था और उन्हें मारकर वहां से भगाता था। वह उनसे बोलता था कि यहां पर सोने की अनुमति नहीं है,कहीं और जाकर तुम रात बिताओ।

रिपोर्टर से मांग कर खाया था खाना

मिमोह ने उस समय के बारे में भी बात की,जब मिथुन चक्रवर्ती को उनके काम के लिए पहचान तो मिल रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी ने तब भी अभिनेता का पीछा नहीं छोड़ा। मिमोह ने कहा,जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए अवॉर्ड जीता था, तो एक रिपोर्टर उन्हें ढूंढकर उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन मेरे पिता कहीं भी नहीं मिल रहे थे। उसे कहीं से ये पता चला कि मिथुन चक्रवर्ती भी उसे ढूंढ रहे हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं। पापा ने बताया था कि वह रिपोर्टर को एक शर्त पर इंटरव्यू देने के लिए राजी हुए थे। उन्होंने रिपोर्टर से कहा था कि मुझे पहले खाना खिला दो,क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था। ये तब की बात है,जब उन्होंने अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था।
मिमोह ने जाते-जाते यह भी बताया कि उनके पिता के संघर्ष ने ही उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि वह क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग को हैंडल कर पाते हैं। अभिनेता ने कहा, मैंने पिता की इस तरह की कई कहानियां सुनी है। जब भी मेरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो ट्रोलिंग हो...या लोगों की बातें,मुझे सिर्फ अपने पिता के वही दिन याद आते हैं।

सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है हॉन्टेड

मिथुन चक्रवर्ती के लाडले महाक्षय चक्रवर्ती ने अपन करियर की शुरुआत साल 2008 में फिल्म जिम्मी से की थी। इसके बाद वह विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड 3डी में आए, जिसके लिए उन्हें तारीफ मिली। अब सालों बाद मिमोह इसी फिल्म का सीक्वल हॉन्टेड 3डी इकोस ऑफ द पास्ट लेकर 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में लौट रहे हैं, जिसके उनके अपोजिट चेतना पांडे हैं।

स्लीवलेस ब्लाउज में श्वेता तिवारी बनी कयामत 45 की उम्र में हॉटनेस देख दीवाने हुए फैंस

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के हाल ही में हॉट लुक वाले लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी धाक जमाने वाली अभिनेत्रियों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें श्वेता तिवारी का नाम भी शामिल होता। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की प्रेरणा बनकर फैंस के दिलों को जीतने वाली श्वेता मौजूदा समय में अपनी लेटेस्ट फोटोज को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं।
जिन्हें उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी स्लीवलेस ब्लाउज में अपनी हॉटनेस का जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही हैं।

सामने आईं श्वेता तिवारी की फोटोज

सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। आए दिन उनकी लेटेस्ट फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी रहती है, जिसकी वजह से सिनेमाई गलियारे में श्वेता का नाम लाइटलाइट बटोरता रहता है। कुछ ऐसा ही कमाल एक बार फिर से श्वेता तिवारी ने करके दिखाया है। दरअसल हाल ही में श्वेता तिवारी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अनसीन तस्वीरों को शेयर किया है, जिनमें वह ब्लैक कलर के स्लीवलेस ब्लाउज और गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं। इस लुक में श्वेता का लुक हद से ज्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रहा है। इन तस्वीरों के जरिए श्वेता तिवारी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि 45 साल की उम्र में भी उनकी हॉटनेस का कोई मुकाबला नहीं हैं और इस मामले में वह बी टाउन की अच्छी-अच्छी एक्ट्रेसेज को मात देती हैं।
आलम ये है कि अब श्वेता तिवारी की ये फोटोज सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों को जमकर लाइक्स और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई यूजर्स श्वेता के इस लुक को देखक उन्हें गोल्डन ब्यूटी करार कर रहे हैं।

इस मूवी में नजर आएंगी श्वेता तिवारी

छोटे पर्दे पर नाम कमाने के बाद अब श्वेता तिवारी बतौर एक्ट्रेस ओटीटी और सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाने के लिए तैयार हैं। बीते समय से श्वेता ने इंडियन पुलिस फोर्स जैसे कई वेब सीरीज के जरिए वाहवाही बटोरी है। गौर करें उनकी अपकमिंग मूवी की तरफ तो उसका नाम वन है, जिसे इसी साल अगस्त के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

खेल समाचार

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम घोषित

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स को इंग्लैंड टीम से ड्रॉप कर दिया गया है...हैरी ब्रूक उपकप्तान हैं लेकिन जो रूट को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है...

नई दिल्ली,10 जून 2026। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित हो गई है। इस टीम में कप्तान बेन स्टोक्स को जगह नहीं मिली है। नाइट क्लब विवाद की वजह से स्टोक्स को टीम में जगह नहीं मिली है। विवाद में उनके साथ तेज गेंदबाज गस एटकिंस भी शामिल थे। उन्हें भी शामिल नहीं किया गया है। ईसीबी ने दोनों खिलाड़ियों के साथ जांच बैठाई है।

जो रूट को मिली इंग्लैंड की कप्तानी

जो रूट को दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड का कप्तान बनाया गया है। 2017 से 2022 के बीच रूट इंग्लैंड टीम की कप्तानी कर चुके हैं। 64 मैचों में उनकी कप्तानी में इंग्लैंड को 27 जीत और 26 साल मिली थी। उन्हें हटाकर ही बेन स्टोक्स को कप्तानी मिली थी। वैसे तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड टीम के उपकप्तान हैं लेकिन बेन स्टोक्स के नहीं होने पर जो रूट को कप्तान बना दिया गया।

जोफा आर्चर और जॉर्डन कॉक्स को जगह

पहले टेस्ट से बाहर रहने वाले जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल की वजह से वह पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। इसके साथ ही जॉर्डन कॉक्स को भी जगह मिली है। आईपीएल 2026 में चैंपियन आरसीबी का हिस्सा रहे कॉक्स ने अभी तक इंग्लैंड के लिए टेस्ट नहीं खेला है। वह इंग्लैंड के लिए 6 टी20 इंटरनेशनल के साथ तीन वनडे मैच खेल चुके हैं।
तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 17 जून से लंदन के ओवल मैदान पर होना है। इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। लॉर्ड्स में हुए पहले टेस्ट को इंग्लैंड ने 115 रनों से अपने नाम किया था।

दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीमः-
जो रूट (कप्तान),रेहान अहमद,जोफ्रा आर्चर,सोनी बेकर,शोएब बशीर,जैकब बेथेल,हैरी ब्रूक,जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट,मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे,जेम्स रेव,ओली रॉबिन्सन,जेमी स्मिथ (विकेटकीपर),जोश टोंग।

वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट सचिन यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से नाम वापस लिया...

नई दिल्ली,10 जून 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत के जैवलिन कैंपेन को एक बड़ा झटका लगा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट सचिन यादव ने कन्फर्म किया है कि कोहनी की चोट के कारण वह इस मल्टी-स्पोर्ट इवेंट से हट गए हैं, जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ने की उम्मीद है। यह खबर 23 साल के इस खिलाड़ी के लिए महीनों की परेशानी के बाद आई है, जो उस फॉर्म को दोहराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसने उन्हें पिछले साल भारत के लीडिंग एथलेटिक्स स्टार्स में से एक बनाया था। यह चोट,जो उन्हें नई दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़-3 के बाद से परेशान कर रही थी,रोम डायमंड लीग में उनके आने के बाद और बिगड़ गई और अब उन्हें कॉम्पिटिशन से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सचिन ने बताया, मैं अभी भी घायल हूं, इसलिए मैंने नाम वापस ले लिया है। मुझे नहीं पता कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में कितना समय लगेगा, क्योंकि मुझे सर्जरी करवानी है। सर्जरी की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है, और चर्चा अभी भी चल रही है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चर्चा करेगा और रिकमेंड करेगा, और जब भी वे हरी झंडी देंगे, सर्जरी होगी। सर्जरी और रिकवरी टाइमलाइन को लेकर अनिश्चितता की वजह से आने वाली इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके हिस्सा लेने पर भी शक है। इस महीने के आखिर में भुवनेश्वर में होने वाली इस मीट का और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह 2026 एशियन गेम्स के लिए एक अहम क्वालिफिकेशन इवेंट है। अगर सचिन इस कॉम्पिटिशन में नहीं खेलते हैं, तो भारत की एशियन गेम्स टीम में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को बड़ी रुकावट आ सकती है।

टी 20 वर्ल्ड कप में दिखेगा भारतीय कनेक्शन

इंग्लैंड ,10 जून 2026। आईसीसी वुमेंस टी 20 वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती अब शुरू हो चुकी है। यह बड़ा टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स की धरती पर खेला जाएगा। दुनिया भर की महिला क्रिकेट टीमें इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी और एक बार फिर रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद की जा रही है। इस टूर्नामेंट में सभी की निगाहें हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर टिकी रहेंगी। भारतीय टीम ने पिछले साल घरेलू सरजमीं पर वनडे वर्ल्ड कप जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। टीम इंडिया इस बार भी मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि इस बार कहानी सिर्फ भारतीय टीम तक सीमित नहीं है। इस विश्व कप में कई ऐसे खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी जो भारतीय मूल की हैं, लेकिन वह अन्य देशों की टीमों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये खिलाड़ी अलग-अलग देशों की जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। क्रिकेट विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक दिलचस्प पहलू है कि भारतीय मूल की खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया,इंग्लैंड,अमेरिका और अन्य देशों की टीमों में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये खिलाड़ी न केवल अपनी फिटनेस और स्किल्स से टीम को मजबूती देती हैं, बल्कि मैच के परिणाम को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।

भारत में फीफा वर्ल्ड कप 12 जून से

नई दिल्ली,10 जून 2026। फुटबॉल का सबसे बड़ा शोपीस इवेंट, फीफा वर्ल्ड कप 2026,12 जून से शुरू होने वाला है। दुनिया भर के फैंस खेल के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी के लिए 48 टीमों के बीच मुकाबला देखेंगे। इस मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को मेक्सिको,कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका मिलकर होस्ट करेंगे और इसमें एक बड़े टूर्नामेंट में कुल 104 मैच होंगे। इस बड़े फॉर्मेट में चार-चार टीमों के 12 ग्रूप शामिल हैं, जो पहले के आठ ग्रूप के स्ट्रक्चर की जगह लेंगे। हर ग्रूप से टॉप दो टीमें,साथ ही तीसरे नंबर पर रहने वाली आठ सबसे अच्छी टीमें, नॉकआउट स्टेज में आगे बढ़ेंगी, जिससे ट्रेडिशनल राउंड ऑफ़ 16 से पहले एक नया राउंड ऑफ़ 32 बनेगा। इंडिया इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन अब तक के सबसे बड़े फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज फैंस में बहुत ज़्यादा है,जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को ग्लोबल स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। इंडिया के दर्शकों के लिए, देश में टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट को लेकर एक रुकावट थी। लेकिन, अब वह रुकावट खत्म हो गई है,और भारतीय दर्शक भी मैच देख सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को नए लॉन्च हुए यूनाईट 8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में 28 बड़े अफसरों का एक साथ तबादला

रायपुर,10 जून 2026। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए 28 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें राज्य के कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य विंग के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से ठीक पहले शिक्षा विभाग में इतने बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों का सीधा असर स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। नए अधिकारियों की नियुक्ति से जिलों में लंबित पड़े शैक्षणिक कार्यों और अटकी हुई फाइलों को गति मिलने की उम्मीद है।

प्रशासनिक कसावट के लिए विभाग ने उठाए कड़े कदम

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई इस तबादला सूची में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को बदला गया है। शासन का मुख्य उद्देश्य मैदानी स्तर पर प्रशासनिक कसावट लाना और नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। तबादला आदेश में कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों सहित विकासखंड शिक्षा अधिकारियोंऔर संयुक्त संचालकों के प्रभार में भी बदलाव किए गए हैं। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को अपनी नई जिम्मेदारी वाले स्थानों पर तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगामी शैक्षणिक गतिविधियों में किसी भी तरह की बाधा न आए। यह स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस थोक तबादले के बाद अगले दो से तीन दिनों के भीतर सभी 28 अधिकारी अपने नए पदों पर जॉइनिंग देंगे। इसके तुरंत बाद जिलों में नए शिक्षा सत्र की तैयारियों, पाठ्यपुस्तक वितरण और शिक्षकों के समायोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं

पीएम मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने छुई नई ऊंचाइयां : सीएम साय

नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार से लेकर किसानों,आदिवासियों,महिलाओं और गरीबों के उत्थान तक केंद्र सरकार का मिला अभूतपूर्व सहयोग

रायपुर,10 जून 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए एक विस्तृत आभार पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व,मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंत्योदय केंद्रित नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में विकास,सुशासन,सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन संभव हुए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की साढ़े तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और सहयोग ने राज्य के विकास को नई गति और नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री साय ने अपने पत्र में सबसे प्रमुख रूप से नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास को समान प्राथमिकता देते हुए जो सहयोग दिया, उससे छत्तीसगढ़ आज नक्सलमुक्ति के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत हजारों करोड़ रुपये की सहायता, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, विशेष अधोसंरचना योजना,आधुनिक हथियारों की उपलब्धता,एयर सपोर्ट और जंगल वारफेयर प्रशिक्षण जैसी पहलों ने सुरक्षा बलों की क्षमता को मजबूत किया। वहीं सड़क,मोबाइल नेटवर्क, बिजली,शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार ने दूरस्थ क्षेत्रों में शासन की पहुंच सुनिश्चित की और स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ाया। पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार की सहायता से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3,222 किलोमीटर से अधिक सड़कों और दर्जनों बड़े पुलों का निर्माण हुआ, जिससे पहले कटे हुए इलाकों तक संपर्क स्थापित हो सका। उन्होंने कहा कि बस्तर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में मजबूत सड़क नेटवर्क के कारण सुरक्षा अभियानों को गति मिली और विकास कार्यों का विस्तार संभव हुआ। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों को मिली वित्तीय मजबूती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने से छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व वित्तीय स्वायत्तता मिली। पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्रीय करों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक तथा विभिन्न योजनाओं के लिए 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त हुई। इसके अलावा जीएसटी क्षतिपूर्ति और पूंजीगत निवेश सहायता जैसी योजनाओं ने राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति दी। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाखों किसानों के खातों में सीधे राशि पहुंची है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, कृषि यंत्रीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 की तुलना में राज्य में पंजीकृत किसानों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है तथा धान खरीदी और किसानों को भुगतान के आंकड़ों में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। साय ने पत्र में आदिवासी विकास को प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि पीएम-जनमन,धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य विद्यालय,वनाधिकार मान्यता और जनजातीय संग्रहालय जैसी पहलें आदिवासी समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पत्रों के वितरण और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है।मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और आजीविका के क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लाखों महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। उज्ज्वला योजना, सक्षम आंगनबाड़ी और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं ने महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री ने उद्योग, खनन और निवेश के क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और सुधारों के कारण छत्तीसगढ़ निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी, रेलवे और सड़क परियोजनाओं का विस्तार तथा औद्योगिक क्लस्टरों के विकास ने रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। पर्यटन,खेल, कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस, दूरसंचार विस्तार,सौर ऊर्जा और आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ विकास के लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

सुशासन तिहार में हंगामा...भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प,कांग्रेसियों ने विधायक वापस जाओ के लगाए नारे

500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का उठाया मुद्दा

रायपुर,10 जून 2026। सुशासन तिहार कार्यक्रम में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू की गाड़ी के सामने लेट गए और वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने हुए। पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र के रावाभाठा,बीरगांव का है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने बीरगांव में सुशासन तिहार शिविर का आयोजन किया था,जिसका विरोध करने कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड के पास कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।

इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी

कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं को आवासीय पट्टा वितरण,500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और महतारी वंदन योजना की राशि से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कार्यक्रम स्थल के आसपास काफी देर तक नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के खिलाफ भी नारेबाजी की।

विधायक का काफिला रोकने का किया प्रयास : कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष पप्पू बंजारे, स्थानीय पार्षदों और अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान विधायक का काफिला भी रोकने का प्रयास किया गया, हालांकि पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर आवागमन सामान्य कराया।

कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष पप्पू बंजारे ने कहा कि उनका प्रदर्शन पूर्व निर्धारित था और इसकी जानकारी पहले से प्रशासन को दी गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने पहुंचे थे। उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया गया।

4 आईएफएस अफसरों का ट्रांसफर

रायपुर,10 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वरिष्ठ स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोलेन्द्र कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वन विभाग में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत ओपी यादव को प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) तथा सह-मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पद पर पदस्थ किया गया है। वर्ष 2001 बैच की वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी शालिनी रैना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे वर्तमान में वन मुख्यालय में प्रशासन, समन्वय तथा राजपत्रित-अराजपत्रित कार्मिकों से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए 3,354 करोड़ रुपए मंजूर 1 जुलाई से लागू होगी 'वीबी जीरामजी'

रायपुर,10 जून 2026। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से लागू किए जा रहे विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 3,354.85 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल किसी योजना में बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका और जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि...एक भी मजदूर बिना काम के न रहे ' और रोजगार उपलब्ध कराने,समय पर मजदूरी भुगतान तथा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पहले ही मनरेगा के लिए 30 हजार करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन घोषित किया गया है। इससे कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह धनराशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे विकास कार्यों की पूर्व स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें,ताकि 1 जुलाई से ही रोजगार सृजन और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके।

बैठक में डिजिटल और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने डीबीटी,ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन और एसएमएस आधारित सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो नई व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

महिलाओं के धर्मांतरण पर सख्त कानून...अपराधियों के प्रति नरमी नहीं

बिलासपुर में दो दिवसीय प्रवास पर कई कार्यक्रमों में शामिल : केंद्रीय मंत्री ठाकुर

बिलासपुर,10 जून 2026। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिला अत्याचार और धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बेटियों के विरुद्ध जघन्य अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मंत्री ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होने बिलासपुर पहुंची थीं। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने शहर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल भले ही विपक्ष के असहयोग के कारण पारित नहीं हो पाया हो,लेकिन भविष्य में इसे पारित कराने का लक्ष्य है। ठाकुर ने महिला सुरक्षा, सुकन्या समृद्धि योजना,आयुष्मान भारत और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मिल रहे लाभों का भी उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने कभी संविधान का पालन नहीं किया, वे आज संविधान की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब अंबेडकर सहित देश के संविधान निर्माताओं की जयंती और पुण्यतिथि पहले कभी नहीं मनाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी नेताओं को पूरे देश में सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक समय ऐसा था जब लोगों को जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता था तो वे तैयार नहीं होते थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कठिन त्याग और संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज पार्टी सत्ता में है। ठाकुर ने प्रधानमंत्री के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री ने एक लाख महिलाओं को राजनीति में लाने का संकल्प लिया है। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक स्वर्णिम युग है।

बिलासपुर के लिए 3 हजार करोड़ की योजनाएं स्वीकृत : अमर

पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में बिलासपुर के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा, अरपा नदी का सौंदर्यीकरण, वृद्धाश्रम निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। वहीं, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है।

गृह विभाग से हटे आईएएस रमेश कुमार शर्मा,सहकारिता आयुक्त की मिली नई जिम्मेदारी

रायपुर,10 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अहम फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रमेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी है। गृह विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत रमेश कुमार शर्मा को अब आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति की है। आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने जारी किया है।

कांग्रेस नेता अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार

दुर्ग,10 जून 2026। महिला के साथ अश्लील हरकत करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कांग्रेस नेता समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता मोनू साहू और उसके साथी महिला से अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम अमलेश्वरडीह का है। इस मामले में अमलेश्वर के पूर्व पालिका उपाध्यक्ष उमेश साहू की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएम भूपेश बघेल के करीबी पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोरध्वज साहू उर्फ मोनू साहू, दीपक वर्मा एवं जय साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। पीड़ित उमेश साहू के अनुसार यह पूरा मामला पुरानी रंजिश और अवैध कब्जे को लेकर शुरू हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भतीजे दुर्गेश साहू पर शासकीय भूमि पर कब्जा करने के आरोप में जन समस्या निवारण शिविर में आवेदन लगाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पटवारी ने भूमि का निरीक्षण किया। इस मामले में अब मोनू साहू और उसके साथी उमेश को ही इसका मुखबिर बताकर धमकी दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक, मोनू साहू और उसके साथी शराब के नशे में 7 जून 2026 की रात लगभग 11 बजे उमेश के घर पहुंचे थे, जहां उमेश साहू की पत्नी अपने घर में परिवार के साथ मौजूद थी। इसी दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य लिखा हुआ कार में सवार होकर कुछ लोग उसके घर के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। घर की घंटी बजाने पर महिला बाहर निकली। आरोप है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोरध्वज साहू उर्फ मोनू साहू, दीपक वर्मा एवं जय साहू ने उसके पति के संबंध में पूछताछ करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गंदे इशारे करते हुए उन्हें धमकी दी।

पति-पत्नी हत्याकांड और लूटकांड,सराफा व्यापारी भी गिरफ्तार

सक्ती,10 जून 2026। जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के सेंदुरस गांव में पति-पत्नी हत्याकांड और लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में दो आरोपियों समेत लूट का माल खरीदने वाले एक सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है।जांच में यह भी सामने आया है कि यही दोनों आरोपी वर्ष 2024 में मुक्ता गांव में हुए चर्चित डबल मर्डर केस में भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार, 2 और 3 जून 2026 की दरमियानी रात सेंदुरस गांव में घर के बरामदे में सो रहे पुरुषोत्तम खुंटे और उनकी पत्नी गुहारिन बाई खुंटे की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद सोने के आभूषण,नकदी और मोबाइल फोन भी गायब मिले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एएसपी पंकज पटेल, एसडीओपी भुवनेश्वरी पैंकरा, साइबर सेल, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम को जांच में लगाया गया। मोबाइल टावर डंप, कॉल डिटेल और सीईआईआर पोर्टल की मदद से पुलिस आरोपी देवकुमार यादव तक पहुंची, जिसके पास से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपने साथी रूपचरण यादव के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। दोनों आरोपी पंडरीपानी गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बताया कि मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर मृतक से विवाद हुआ था। इसी रंजिश में उन्होंने स्केल पट्टी से दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया और सो रहे दंपती के सिर व चेहरे पर लोहे की रॉड से कई वार कर हत्या कर दी। इसके बाद सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रूपचरण के घर से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, खून से सने कपड़े और 74 हजार रुपए बरामद किए। वहीं लूटे गए आभूषण जैजैपुर के खिलेश्वर ज्वेलर्स संचालक बाबूलाल साहू को 84 हजार रुपए में बेचे गए थे। पुलिस ने बाबूलाल साहू को भी गिरफ्तार कर आभूषण बरामद कर लिए हैं।

कोरबा में एक के बाद एक ब्लास्ट पटाखा गोदाम में लगी आग

कोरबा,10 जून 2026। जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के रामपुर स्थित एक पटाखा गोदाम में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग लगते ही गोदाम में रखे पटाखों में लगातार विस्फोट होने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के दौरान आसमान में धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार, रामपुर स्थित शर्मा पटाखा गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें देखते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गोदाम में रखे पटाखों के फटने से लगातार तेज धमाके सुनाई देते रहे, जिससे आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि आग की भयावहता को देखते हुए अन्य क्षेत्रों से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को घेरकर लोगों को दूर रखा जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)